स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

वर्ष–24, अंक–1
पौष–माघ 2072, जनवरी 2016

संपादक
विक्रम उपाध्याय

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 34-37

कवर तृतीय पेज 39
कवर चतुर्थ पेज 40

आवरण कथा – पृष्ठ–6

12वां अखिल भारतीय सम्मेलन

1 कवर पेज
2 कवर द्वितीय पेज

16 समीक्षा
दवाईयों के पेटेंट पर केन्द्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य
..... **प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा**

18 डब्ल्यूटीओ
नैरोबी सम्मेलन – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गैर बराबरी की लड़ाई
..... **डॉ. अश्वनी महाजन**

20 डब्ल्यूटीओ
कृषि मसले सुलझाने में नैरोबी भी हुआ फेल
..... **रणवीर सिंह**

22 कसौटी
किसका विकास?
..... **डॉ. भरत झुनझुनवाला**

24 विचार
स्वदेशी तकनीक का विकास करें
..... **निरंकार सिंह**

26 आतंकवाद
कब तक सहेंगे पीठ पर वार
..... **धर्मेन्द्र भदौरिया**

28 पर्यावरण
पेरिस जलवायु समझौता – यह इश्क नहीं आसां
..... **अरूण तिवारी**

33 कृषि
जलवायु परिवर्तन से कृषि क्षेत्र का विकास प्रभावित
..... **गार्गी परसाई**

38 रिपोर्ट
बाबू गेनू बलिदान दिवस सभा
..... **स्वदेशी संवाद**

पाठकनामा

योजनाएं जमीन पर कब तक?

मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से लगातार सुनते आ रहे हैं कि देश में विदेशी पूंजी निवेश खूब हो रहा है, कहीं 'मेक इन इंडिया' का नारा बुलंद किया जा रहा है, तो कहीं 'स्किल इंडिया' की चर्चा जोरों पर है। अफसोस है कि किसान भूखे मर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार के लिए दर–दर भटकना पड़ रहा है। उद्योग जगत त्राहि–त्राहि कर रहा है और आम जनता बमुश्किल महंगाई का सामना कर पा रही है। आखिर इतनी सारी घोषणाओं का क्या मतलब? जब धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि योजनाएं जमीन पर कम तक नजर आयेंगी, सरकार के दो वर्ष पूरे होने को है, आशा कहीं निराशा में न बदल जाए।

सुनील तिवारी, *छत्तीसगढ़*

*****

पाक से वार्ता तत्काल रोकें

देश के जवान हमारी धरती पर ही लहूलुहान हो रहे हैं। सीमा पार से आए आतंकवादी हमारी संप्रभुत्ता को चुनौती दे रहे हैं। 6 महीने के भीतर कश्मीर और पंजाब में आतंकवादियों ने 4 बड़े हमलों को अंजाम दिया है। ये चारों हमले हमारी सेना और महत्त्वपूर्ण सैन्य ठिकाने पर किए गए हैं। इसके बावजूद हम पाकिस्तान से दोस्ती की अपेक्षा कर रहे है, जबकि पाकिस्तान दोस्ती की भाषा समझता ही नहीं। अच्छा रहता, यदि हम पाकिस्तान को उसके किए का सबक सिखाते, आतंकवादी गढ़ों को ध्वस्त कर देते। अफसोस, हमारी सरकार अभी भी बातचीत के लिए राजी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की लाहौर यात्रा के बाद पठानकोट पर हमला उसी तरह का है, जैसा प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की लाहौर यात्रा के बाद कारगिल का हमला हुआ था। हम यह क्यों नहीं मानते कि पाकिस्तान में परदे के पीछे से हुकूमत करने वाली वहां की सेना और उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत–पाकिस्तान के बीच कभी भी दोस्ती नहीं होने देंगी। वार्ता तुरंत रद्द कर देनी चाहिए।

श्याम खोसला, *दिल्ली*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

प्रधानमंत्री ने लाहौर जाकर बिल्कुल सही काम किया।

नीतिश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

अयोध्या में इस वर्ष के अंत तक राम मंदिर का निर्माण जरूर शुरू होगा।

सुब्रह्मण्यम् स्वामी

बीजेपी नेता

अमरीका में बंदूक संस्कति ने छोटे-छोटे बच्चों को अपना निवाला बना लिया है।

बराक ओबामा

राष्ट्रपति, अमरीका

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने विजन को हकीकत में बदलने के लिए सही वैज्ञानिक सलाह की जरूरत है।

भारत रत्न, **प्रो. सी.एन. राव**

वक्त आ गया है कि अब मुस्लिम कट्टरवाद पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

तस्लीमा नसरीन

लेखिका, बंग्लादेश

संपादकीय

बाहर ही नहीं, भीतर से भी खतरा!

लगातार गिरफ्तारियां और रोज खुलासे एक तरफ ऐसा आभास देते हैं कि भारत की रक्षा प्रणाली एक दम दुरूस्त और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह चौकन्नी हैं, लेकिन एक के बाद एक आतंकी घटनाएं और सीमा पार से तस्करी कर आ रहे हथियार और मादक पदार्थ हमारी लचर आतंरिक सुरक्षा के बारे में भी उतने ही मजबूत सबूत पेश करते हैं। जबसे नरेन्द्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है तब से सैकड़ों अताताई जेल के भीतर डाले जा चुके हैं। 2014 में 77 ऐसे लोग पुलिस और सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े जिनका इस्लामी आतंकवाद से कहीं न कहीं संबंध रहा। 2015 में भी नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से होकर आने वाले देश के दुश्मनों की संख्या 170 से ऊपर रहीं। जो प्रमुख आतंकवादी गिरफ्तार किए गए उनमें, इंडियन मुजाहिद्दीन का चीफ यासीन भट्टकल, उसके बाद बने नये प्रमुख पाकिस्तान का जियाउर रहमान उर्फ वकास और अब्दुल करीम टुंडा भी रहा। चिंता की बात यह है कि भारत को कमजोर करने में लगे दुश्मनों की उपस्थिति पूरे देश में बनी हुई है। कोई चेन्नई से गिरफ्तार हो रहा है तो कोई जयपुर और जोधपुर से। आईबी के एक डायरेक्टर आसिफ इब्राहिम का कहना है कि पाकिस्तान का लश्कर–ए–तोइबा और इंडियन मुजाहिदीन ने अपना नेटवर्क इतना बढ़ा लिया है और इतनी ताकत हासिल कर ली है कि कम समय की तैयारी में ये भारत में कहीं भी और कभी भी हमला कर सकते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा में कितनी सेध लग चुकी है उसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि देश के 640 जिलों में से 205 जिले किसी न किसी प्रकार के आंतकी घटनाओं से प्रभावित हैं। 120 जिलों में माओवादी पसरे हुए हैं और लगातार सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बना रहे हैं तो कश्मीर के 20 जिलों में पाकिस्तान से सहायता प्राप्त कई आतंकवादी गुट लगातार खून खराबे कर रहे हैं। देश के छह पूर्वोत्तर राज्यों के 65 जिलों में जातिवादी और अतिवादी संघर्ष चल रहा है तो उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों से आंतकवाद की पौध निकल रही है।

26/11 की घटना के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर व्यापक बहस हुई थी, उसी समय यह तय किया गया था कि देश पर आसन्न खतरे को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद किया जायेगा। आधुनिक उपकरणों के साथ–साथ जरूरी संख्या में मानव संसाधन को भी तैनात किया जायेगा। लेकिन पांच साल के बाद भी देश की आतंरिक सुरक्षा की तैयारियां पूरी नहीं हो पाईं। आईबी में अफसरों की भारी कमी है। देश में 26,867 आईबी अफसरों की नियुक्ति की संस्तुति है लेकिन इस समय लगभग 8000 पद खाली हैं। जाहिर है या तो मौजूदा आईबी अफसरों पर काम का बहुत दबाव है या फिर पूरे देश पर उनकी पकड़ नहीं है। आईबी में ही अफसरों का टोटा नहीं है, पुलिस बल में भी उपयुक्त संख्या में अधिकारी नहीं है। पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए सीधे जिम्मेदार आईपीएस अफसरों की संख्या भी नाकाफी है। पूरे देश के लिए 4730 आईपीएस अफसरों की नियुक्ति होनी चाहिए लेकिन इस समय भी लगभग एक हजार आईपीएस अफसरों की कमी देश में है। एक लाख की जनसंख्या पर केवल 106 पुलिस की व्यवस्था किसी देश की कानून व्यवस्था अकेले नहीं संभाल सकती। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में यह पुलिस पब्लिक अनुपात 60 के आस पास ही है। केवल साधनों और संसाधनों की ही कमी नहीं है। हमारे यहां एप्रोच और ईमानदारी की भी भारी कमी है। आए दिन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के इस आरोप के साथ पकड़े जाने की खबरे आ रही हैं कि पैसे के लिए उन्होंने दुश्मन देश को हमारी सुरक्षा से संबंधित जानकारियां बेच दी। पठानकोट हमले के लिए पाकिस्तान को सहायता पहुंचाने और अपनी सुरक्षा तैयारियों को जानकारी आतंकवादियों तक पहुंचाने के मामले में बीएसएफ के जवान से लेकर भारतीय वायु सेना में शामिल रहें लोगों तक के नाम आ रहे हैं।

हमारे देश में बहु स्तरीय एजेंसियों के बीच तालमेल और संयुक्त अभियान में भारी घालमेल दिखाई देती है। देश में कई खुफिया एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं। जैसे रिसर्च व एनालिसिस विंग (रॉ), नेशनल टेक्नीकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी, और एसआईबी। इन सबकी सुचनाएं एक साथ 'दि मल्टी एजेंसी सेंटर' यानी 'मैक' में आकर जमा होती हैं फिर भी हमारे यहां आतंकवाद या उग्रवाद पर कोई राष्ट्रीय डाटा बेस नहीं होता। इससे न तो अपराधियों की गतिविधियों की ट्रेकिंग हो पाती है और न उनके खिलाफ कोई कारगर प्लान बन पाता है। यहीं नहीं 1996 में ही देश के सभी थानों को एक दूसरे से जोड़ने की योजना को हरी झंडी दे दी गई थी। इस पर अरबों रुपये खर्च भी हो गए। लेकिन अब भी यह योजना कारगर नहीं है और न जाने इस पर कितने वर्ष और लग जाएंगे। यही हश्र नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का भी हुआ है। इस ग्रिड की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि इसके जरिए बैंकों और अन्य वित्तीय स्रोतों के जरिए आतंकवादियों को दी जा रही वित्तीय मदद की जानकारी और उसकी ट्रैकिंग की जा सकेगी। इस पर भी अरबों रूपये खर्च किए जा चुके हैं पर इस ग्रिड के अस्तित्व में आने की तारीख का पता नहीं।

१२वां अखिल भारतीय सम्मेलन

स्वदेशी जागरण मंच का त्रीदिवसीय १२वां अखिल भारतीय सम्मेलन शिक्षा, संस्कति और आर्थिक चिंतन के सतत् प्रवाहों के साथ २५ दिसंबर २०१५ को जोधपुर (राजस्थान) के श्री हनवंत आदर्श विद्या मंदिर में शुरू हुआ।
– स्वदेशी संवाद

राजस्थान वीरों की भूमि है। 15वीं शताब्दी में जोधा राव द्वारा स्थापित जोधपुर सूर्य नगरी और धर्मनगरी के नाम से मशहूर है, जहां स्वदेशी जागरण मंच का 12वां अखिल भारतीय स्वदेशी सम्मेलन शिक्षा, संस्कृति और आर्थिक चिंत्तन के सतत् प्रवाहों के साथ 25 दिसंबर 2015 को शुरू हुआ।

स्वदेशी जागरण मंच के 12वें राष्ट्रीय सम्मेलन से एक दिन पूर्व जोधपुर के श्री हनवंत आदर्श विद्या मंदिर में राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' ने तीन दिवसीय स्वदेशी राष्ट्रीय सम्मेलन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि तीन दिवसीय सम्मेलन में कुल सात सत्र, चार विशेष व्याख्यान, आर्थिक, देशी चिकित्सा, महिला और कृषि विषय पर चार समानांतर सत्र, स्वदेशी संदेश यात्रा तथा हुंकार सभा सहित सतत् विकास, शिक्षा, विश्व व्यापार संगठन और मेड बाई इंडिया विषयों पर चार प्रस्ताव पारित किए जायेंगे।

उत्तर प्रदेश और उतरांचल के क्षेत्र संयोजक श्री संजीव महेश्वरी ने वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम (जीएसटी) विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा कहा कि इसके कानून बनने और लागू होने के पश्चात् आम जनता पर इसके प्रभावों का आकलन किया जाना बाकी है। राष्ट्रीय सम्मेलन में रखे जाने वाले शिक्षा, सतत् विकास, विश्व व्यापार संगठन तथा मेड बाई इंडिया प्रस्तावों पर चर्चा की गई। प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी, दिल्ली के श्री विक्रमजीत बैनर्जी तथा स्वदेशी पत्रिका (अंग्रेजी) के संपादक ने प्रस्तवों का वाचन किया।

विश्व व्यापार संगठन की नैरोबी में आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक से लौटे मंच के अखिल भारतीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने बताया कि सम्मेलन में भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों का विकसित देशों ने प्रबल विरोध किया। उन्होंने बताया कि सभी देश दोहा डवलपमेंट के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते थे, किन्तु कुछ विकसित देशों की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में शमिल स्वदेशी जागरण मंच के

प्रस्ताव – 1

सतत् विकास–समय की मांग

ग्लोबल वार्मिगं और जलवायु परिवर्तन हर बीतते वर्ष के साथ बहुत तेजी से क्रूर एवं नुकसानदेह होता जा रहा है। W.M.O. ने अभी हाल ही में ही कहा है कि सन 2015 अभिलेखों के अनुसार अभी तक का सबसे गर्म वर्ष था। यदि हम गत 150 वर्षों के सबसे गर्म 15 वर्षों की सूची बनाएं तो वे समस्त 15 वर्ष सन 2000 के बाद अर्थात 21वीं शताब्दी के ही वर्ष होगें। यह तथ्य 21वीं शताब्दी में ग्लोबल वार्मिगं की समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। भूमंडल के बढ़ते हुए तापमान से गंभीर मौसमी आपदाएं जैसे कि कुछ सीमित क्षेत्रों में तेज और भारी वर्षा, जैसाकि नवम्बर एवं दिसम्बर माह में चैन्नई और इसके आस पास के इलाके में देखी गयी एवं देश के बाकी हिस्सों में गंभीर सूखे की समस्या के प्रकोप में लगातार वृद्धि के आसार दिखायी दे रहे हैं। चैन्नई में आई बाढ़ ने प्रकृति के रोष के समक्ष मानव की लाचारी एवं मानवीय संस्थाओं की असफलता को हमें दृष्टिगत कराया है। अगर साल दर साल, इसी प्रकार से अनेक नगर एक साथ प्राकृतिक आपदा के कारण मुश्किल में आते हैं, तब कौन किसकी सहायता कर पायेगा?

सम्पूर्ण विश्व अपनी ही गल्तियों का स्वंय ही शिकार बन चुका है। अस्थायी विकास का मॉडल जोकि पश्चिमी देशों में सन 1850 से प्रारम्भ हुआ और जिसका विश्व के सभी देशों ने बिना सोचे समझे अनुसरण किया, यही इस वैश्विक जलवायु संकट का प्रमुख कारण है। विकास का पश्चिमी मॉडल टिकाऊ नहीं है क्यूंकि 160 वर्षों के छोटे से कालखंड में ही, सन 1850 जबसे यह प्रारम्भ हुआ, सम्पूर्ण विश्व को इस विनाश के कगार बिन्दु पर ले आया है। आज के वैश्विक तापमान में औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व के वैश्विक तापमान से मात्र 1C की वृद्धि ही हुई है। जलवायु स्थिति हमारे नियन्त्रण से बाहर होती है, जैसाकि केवल 1C पर हुआ है, तो भविष्य में वैश्विक तापमान में यदि 2C या अधिक की वृद्धि होती है, तो क्या होगा?

विकास का पश्चिमी मॉडल उसी प्रकार के लचर असीमित उपभोग के मॉडल पर आधारित है और इस पर ही मजबूती से निर्भर करता है। यह लालच और अदूरदर्शिता है। WWF के द्वारा तैयार की गई लिविगं प्लेनेट रिपोर्ट–2014 का स्पष्ट कहना है कि सन 1970 से विश्व के जंगली जानवरों की आधे से अधिक संख्या उनका अधिक और अवैद्य शिकार किए जाने, उनकी मारे जाने और उनके रहने के स्थान में आए संकुचन के चलते कम हुई है। उसका आगे कहना है कि यदि सम्पूर्ण विश्व अमेरिका की भांति संसाधनों के अत्यधिक उपभोग के स्तर को बनाऐ रखता है तो हमें संसाधनों की आपूर्ति के लिए चार और पृथ्वियों की आवश्यकता पड़ेगी। इससे सिर्फ पश्चिमी जीवन शैली का खोखलापन सिद्ध होता है।

आखिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? वर्तमान पश्चिमी विकास एवं जीवन शैली के मॉडल से प्रतीकात्मक एवं गड्डमड्ड समझौता विश्व को बिल्कुल भी बचाने नहीं जा रहा। हमको अधिक सौम्य और अधिक स्थायी तरीके से विकास एवं जीवनशैली के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। विकास एवं जीवनशैली के टिकाऊपन का एक सजीव एवं प्रमाणित उदाहरण विकास का भारतीय मॉडल है जिसे विकास एवं जीवनशैली का स्वदेशी मॉडल भी कहा जा सकता है। स्वदेशी मॉडल इस अर्थ में सम्पूर्णता लिए हुए है कि यह जीवन (धर्म एवं मौक्ष) में भौतिकता (अर्थ, काम) एवं आध्यात्मिकता को समान महत्व देता है। यह पृथ्वी मां को उसके चेतन एवं अचेतन, समस्त स्वरुपों में अत्यन्त सम्मान एवं श्रद्धा देती है।

स्वदेशी विकास की अवधारणा भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण उपभोग की वकालत होती है। आज समय की मांग है कि न केवल भारत अपितु पूरे विश्व को विनाश से बचाने के लिए सहस्राब्दी से प्रमाणित एवं सफलतापूर्वक संचालित स्वदेशी की विकास की अवधारणा और जीवन शैली को अपनाया जाए।

जोधपुर (राजस्थान) में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन मांग करता है कि –

1. टिकाऊ विकास का भारतीय मॉडल एवं जीवन शैली से संबंधित विभिन्न आयामों पर विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के द्वारा व्यापक एवं स्तरीय शोध कार्य को प्रोत्साहन दें।
2. विशेषकर विश्वविद्यालद्यों एवं विषय पर स्वयंभू तज्ञयों के बीच शोध के परिणामों को व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित करें।
3. शोध के परिणामों के आलोक में सरकार की विकास प्राथमिकता निश्चित हो।
4. COP-21 को भारत सरकार द्वारा सौंपी गई INDC के अनुरूप अक्षुण ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता दी जाए।
5. जैविक खेती एवं पशुपालन को प्रचारित एवं प्रसारित करने हेतु योग्य कदम उढाया जाए।
6. वृक्षारोपण, विशेषकर स्वदेशी किस्म के फलदार वृक्षों का व्यापक आंदोलन चलाया जाए, ताकि वन जीव–जंतुओं को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध रहे।

स्वदेशी जागरण मंच देश की जनता से भी विशेषकर स्वदेशी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता है कि वे प्रकृति के प्रति संवेदनशील उद्यमता एवं जीवन शैली को अपनाए। ❑

सात कार्यकर्ताओं ने धरना और प्रदर्शन के माध्यम से भारत का मुख्यतः किसानों का पक्ष रखा।

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में आयोजित सम्मेलन से लौटे राजस्थान प्रांत के संयोजक श्री भगीरथ चौधरी ने विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया किा कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा डेढ़ डिग्री तक तापमान कम करने के लिए वैश्विक सहमति बनी तथा इसके लिए सभी देशों ने धन व तकनीकी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

प्रस्ताव – 2

'मेड बाई भारत' से ही देश का विकास संभव

स्वदेशी जागरण मंच इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है कि विगत 24 वर्षों में आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत आयातों में उदारीकरण से आज जहाँ देश आयातित वस्तुओं के बाजार में बदल गया है, वहीं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को प्रोत्साहन देते चले जाने से देश के सगंठित क्षेत्र के उत्पादन तंत्र के दो तिहाई से भी अधिक अंश पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्वामित्व व नियन्त्रण होता चला गया है। आयातों में अथाह बढ़ोतरी के कारण ही सरकार को चालू खाते के घाटे की पूर्ति के लिये नये–नये क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों को राष्ट्रीय हितों के विपरीत शर्त्तों पर प्रोत्साहन देना पड़ रहा है। अधिकांश उद्योगों में शत–प्रतिशत विदेशी निवेश के स्वतः अनुमोदन की नीति के परिणामस्वरूप देश के औद्योगिक उत्पादन तंत्र में 2/3 से अधिक विदेशी कंपनियों का वर्चस्व हो गया है। शीतल पेय, टूथपेस्ट, जूते के पॉलिश से लेकर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, स्वचालित वाहन, सीमेन्ट सहित दूर संचार व ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के निर्माण तक के 2/3 भाग पर आज विदेशी कम्पनियां हावी हैं। प्रश्न यह उभरता है कि इस देश के उत्पादन के साधनों पर अब किसका नियंत्रण होगा? भारतीयों का अथवा विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का?

उदाहरणतः वर्ष 1999 के पूर्व देश में सारा सीमेन्ट भारतीय स्वदेशी उद्यम बनाते थे। देश में निर्माण कार्यों में उछाल आने की आशा में यूरोप के छह बड़े सीमेन्ट उत्पादकों ने दक्षिण पूर्व एशिया के कोरिया आदि देशों से सस्ती सीमेन्ट भेजना कर प्रारंभ कर हमारे देश में स्थानीय सीमेन्ट उत्पादकों को दबाब में लाकर उनको उद्यम बिक्री को बाध्य करके आज हमारी आधी से अधिक सीमेण्ट उत्पादन क्षमता पर कब्जा कर लिया है। टाटा के टिस्को के सीमेन्ट के कारखाने और देश भर में फैले एसीसी व गुजरात अम्बुजा आदि के संयंत्रों के यूरोपीय कम्पनियों लाफार्ज व हॉलसिम द्वारा अधिग्रहण के बाद आज देश की दो तिहाई सीमेन्ट उत्पादन क्षमता यूरोपीय सीमेन्ट उत्पादकों के स्वामित्व व नियंत्रण में गयी है। सौर ऊर्जा जनन के क्षेत्र में विदेशी निवेश व आयात उदारता के कारण देश के सुस्थापित उद्यम भी बंद हो रहे हैं। सूती वस्त्रोंद्योग के निर्यातों में भारत बांग्लादेश से भी पिछड़ रहा है।

इसी प्रकार आर्थिक सुधारों के प्रारम्भ होने पर प्रथम पीढ़ी की दूर संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश सर्वथा स्वावलम्बी था और हमारी प्रौद्योगिकी मोटोरोला व सीमेन्स जैसी यूरो–अमेरिकी कम्पनियों के समतुल्य थी। लेकिन, आयात उदारीकरण के कारण और उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास की ओर उपेक्षा के कारण देश दूसरी, तीसरी व चौथी पीढ़ी की दूर संचार प्रौद्योगिकी में पूरी तरह पराश्रित हो गया है। यही स्थिति उच्च प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्रों में भी हो रही है। इसीलिये उत्पादक उद्योगों के कुल वैश्विक उत्पादन (World manufacturing) में भारत का अंश मात्र 2.04 प्रतिशत ही है, जबकि इसमें चीन का अंश 23 प्रतिशत है। वर्ष 1992 में चीन का अंश भी मात्र 2.4 प्रतिशत ही था। आज उसने अमेरिका को भी 17.5 प्रतिशत के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर पहुँचा कर उत्पादक उद्योगों के उत्पादन (World manufacturing) में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। यह सब हमारे उदार आयातों व विदेशी निवेश को दिये जा रहे अनुचित प्रोत्साहन का परिणाम है, हम इतने पिछड़ते जा रहे हैं।

कई उद्योगों में हमारा आज विश्व के उत्पादन में अत्यन्त स्वल्प व हास्यास्पद अंश है, यथा वैश्विक जलपोत निर्माण (world ship building) में हमारा मात्र 0.01 प्रतिशत अंश ही है। जबकि हम विश्व के चौथे बड़े स्पात उत्पादक देश हैं, 6100 किमी लम्बी हमारी तट रेखा है और 2009 में हमारा अंश कम से कम 1.4 प्रतिशत तो था। दूसरी और दवा उद्योग में उचित वातावरण प्रदान करने से आज विश्व के कुल औषधि उत्पादन में हमारा अंश 10 प्रतिशत होने से हम विश्व की फार्मेसी (Pharmecy of the world) कहलाते है और विश्व के जरूरतमन्द लोगों के लिये सस्ती दवाओं का विश्व में एकमेव स्त्रोत है। वहाँ आज हम हम यूरो–अमेरीकी दबाव में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के नाम पर स्वदेशी उद्यमों के विकास का मार्ग अवरूद्ध करते जा रहे हैं। अन्य भी अनेक विधिक परिवर्तनों से छोटे उद्यमों के लिए ऐसी बाधाये खड़ी की जाती रहीं हैं, कि, सभी क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों के लिये कारोबार में कई बाधायें अनुभव की जा रही हैं। इसी क्रम में सौर व पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में देश में 10 लाख करोड़ का निवेश अपेक्षित है। इसलिए सामान्य उपभोक्ता उत्पादों से अवसंरचना क्षेत्र पर्यन्त 'मेड बाई इंडिया' का अनुसरण कर देश में ही सभी उत्पादों व ब्राण्ड्रों के प्रवर्तन को समर्थन देना होगा।

इसलिये स्वदेशी जागरण मंच आवाहन करता है कि देश के इलेक्ट्रोनिक्स सेमीकण्डक्टर उद्योग सौर ऊर्जा संयंत्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से लेकर वस्त्रोद्योग पर्यन्त सभी उद्योगों के क्षेत्र में कार्यरत उद्यम संगठित होकर उनके अपने उद्योग सहायता संघों (Industry Consortium) का विकास कर मेड बाई इण्डिया उत्पाद व ब्राण्ड विकसित करें। आज देश में 400 प्रमुख उद्योग संकुल (Major Industry Clusters) 7000 लघु संकुल (Minor Clusters) हैं। इन उद्योग संकुलों (Industry Clusters) को उद्योग सहायता संघों (Industry consortiums) में बदलना, उनके लिये प्रौद्योगिकी विकास सहकारी संघों या प्रौद्योगिकी विकास सहकारी समझौतों की योजना करना आदि मेड बाई इण्डिया के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आज की अनिवार्य आवश्यकता है।

वस्तुतः देश के प्रत्येक उद्योग केन्द्र पर उद्योग संकुलों एवं सभी उद्योगों यथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों व सौर ऊर्जा संयंत्र निर्माताओं से लेकर वस्त्राद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स व सेमिकण्डक्टर उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में उत्पादकों के स्व–नियामक 'मेड बाई इण्डिया फोरम या संघ' विकसित करके ही विदेशी प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर उनके प्रभाव व वर्चस्व को सीमित करने का एक श्रेयस्कर मार्ग सिद्ध हो सकता है। समाज में स्वदेशी भाव जागरण के साथ–साथ स्वदेशी उद्यमों को विदेशी उद्यमों के सम्मुख बेहतर स्पर्द्धाक्षम बनाने के लिये संगठित करने के लिए आवाहन करता है। साथ ही सरकार को भी चेतावनी देता है कि आयात व विदेशी निवेश प्रोत्साहन से मेक इन इंडिया के स्थान पर मेड़ बाई इंडिया के श्रेयस्कर मार्ग को प्रोत्साहन दे। ❑

प्रस्ताव – 3

कृषि निवेश और पेटेंट व्यापार वार्ताओं से बाहर किया जाए

नैरोबी (कैन्या) में 19 दिसंबर 2015 को संपन्न विश्व व्यापार संगठन के मंत्री सम्मेलन में जिस प्रकार से विकासशील देशों के हितों के विपरीत दोहा विकास चक्र को तिलांजली दे दी गई और विकसित देशों द्वारा कृषि को दी जाने वाली भारी सब्सिडी के चलते आयातों की बाढ के फलस्वरूप हमारे किसानों और कृषि को भारी संकट से बचाने हेतु विशेष बचाव उपायों (एसएसएम) और खाद्य सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा खाद्यान्न खरीद पर सब्सिडी गणना की गलती को सुधारने हेतु समाधान देने में भी विकसित देशों की आनाकानी से यह स्पष्ट हो गया है कि विश्व व्यापार संगठन में हुए पूर्व के समझौतों से विकासशील देशों और विशेष तौर पर भारत को भारी कठिनाईयों से गुजरना पड़ रहा है। विदेशों से सब्सिडी युक्त कृषि पदार्थों की बाढ के कारण हमारे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता और कृषि लगातार अलाभकारी होती जा रही है और हमें अपनी गरीब जनता की खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री ने भी कहा है कि दोहा विकास चक्र को आगे बढाने में असफल होने के कारण वे अत्यन्त निराश है।

यह एक खुला सत्य है कि विश्व व्यापार संगठन के बनने के समय हुआ मराकेश समझौता विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर दबाव बनाकर उनके हितों के विपरीत करवाया गया, जिसमें कृषि, निवेश, पेटेंट और सेवाओं जैसे विषयों को शामिल करते हुए, विकासशील देशों के शोषण का तंत्र तैयार किया गया। 'ट्रिप्स' के नाम पर बाध्यकारी समझौता करते हुए भारत और अन्य देशों को अपना पेटेंट कानून बदलने के लिए बाध्य किया गया ताकि अमरीका और अन्य विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों के पेटेंट अधिकारों के बदले में उन्हें अधिकाधिक रायल्टी मिल सके। ऐसे में कहा गया कि दवाईयां तो मंहगी होगी लेकिन हमारे किसानों को इस समझौते से लाभ होगा क्योंकि वे विकसित देशों को अपने उत्पादों को निर्यात कर सकेंगे। लेकिन मराकेश समझौते में दिए वचन से मुकरते हुए विकसित देशों ने अपनी कृषि सब्सिडी को घटाने के बजाए 'ग्रीन बॉक्स' के नाम पर उसे और बढा दिया। विकसित देशों ने अपनी सब्सिडी को घटाया नहीं और भारत में खाद्य सुरक्षा हेतु किसानों से सीधा अनाज की खरीद पर विश्व व्यापार संगठन में आपत्ति जरूर दर्ज कर दी।

मराकेश में हुए ट्रिप्स समझौते के कारण आज विकसित देशों की दवा निर्माता बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों द्वारा दवाईयों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। लेकिन उस समझौते में उपलब्ध लचीलेपन जैसे इन कम्पनीयों द्वारा गलत तरीके से पुनः पेटेंटीकरण पर रोक, अनिवार्य पेटेंट की सम्भावनाओं, पेटेंट पूर्व आपत्ति दर्ज करने के प्रावधान और पेटेंट लेने से पहले क्लीनिकल ट्रायल आंकड़ों को उपलब्ध कराने की अनिवार्यता आदि को समाप्त करवाने के लिए विकसित देश, विशेष तौर पर अमरीकी सरकार, भारत सरकार पर दबाव बना रही है। प्रधानमंत्री जी की अमरीका यात्रा के दौरान भारत–अमरीका सयुंक्त कार्यदल और साथ ही साथ 'थिंक टैंक' की निर्मिति के माध्यम से भारत और अन्य विकासशील देशों को प्राप्त सुविधा को समाप्त करवाने का प्रयास हो रहा है।

स्पष्ट है कि मराकेश समझौते के कारण हमारी कृषि और किसान ही नहीं बल्कि आम जन की खाद्य सुरक्षा भी गंभीर संकट में है। दवाईयां मंहगी होने के कारण हमारा जन–स्वास्थ्य ही खतरे में नहीं है, बल्कि ट्रिप्स में उपलब्ध छूटों के कारण हमारी स्वदेशी दवा कंपनियां, जो 200 से भी ज्यादा देशों को सस्ती दवाईयां निर्यात कर विकासशील देशों की ही नहीं बल्कि विकसित देशों की गरीब जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन कर रही हैं, के उत्पादन को भी बाधित करने का प्रयास हो रहा है।

इन परिस्थितियों में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सम्मेलन का यह सुविचारित मत है कि मराकेश के असमान और शोषणकारी समझौते से उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में राष्ट्रीय बहस और विगत 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर सरकार एक व्यापक समीक्षा करवाए। देश की कृषि और विज्ञान को बचाने, जनस्वास्थ्य और उद्योगों की रक्षा हेतु कृषि 'ट्रिप्स' और 'ट्रिप्स' (विशेष तौर पर पेटेंट) को विश्व व्यापार संगठन से बाहर करवाने हेतु सघन प्रयास किए जाए। विश्व व्यापार संगठन में राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर विकसित देशों के दबाव में आकर किसी प्रकार का समझौता न करें। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत विकासशील देशों का नेतृत्व करते हुए विश्व व्यापार संगठन में आमूल बदलाव के लिए आगे बढ़े।

यह स्मरण कराते हुए कि विश्व व्यापार संगठन में सभी निर्णय सर्वसम्मति से होते है स्वदेशी जागरण मंच का यह राष्ट्रीय सम्मेलन इस बात पर बल देता है कि मिडिया में क्षोभ व्यक्त करने के स्थान पर वार्ताकक्ष में दोहा वार्ता की भांति अपना पक्ष दृढतापूर्वक रखते हुए उस पर अडिग रहना चाहिए। ❑

उत्तर क्षेत्र संगठक श्री सतीश कुमार ने सौर उर्जा पर विषय रखा और बताया कि प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में स्वदेशी के कार्यकर्ताओं का 'सोलर एनर्जी डवलपमेंट फोरम' का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि अगले दस वर्षों में भारत में सौर उर्जा के क्षेत्र में दस लाख करोड़ रूपये का नियोजन होने की संभावना है, यह देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकता है।

राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की तथा आगामी कार्यक्रमों के लिए कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए। राष्ट्रीय संयोजक श्री अरूण ओझा ने अगले वर्ष के लिए राष्ट्रीय सभा के विषय पर चर्चा की। राष्ट्रीय परिषद के देशभर से आये सदस्यों, केंद्रीय व प्रांत के पदाधिकारियों

प्रस्ताव – 4

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हो

व्यक्ति के व्यक्तित्व को, समाज की पहचान को एवं देश की प्रतिष्ठा को निखारने का एक सशक्त साधन है, शिक्षा। इसी उद्देश्य से शिक्षा–नीति निर्धारित हो तो वह अधिक परिणामकारी व फलदायी होगी इसमें कोई संदेह नही। स्वदेशी जागरण मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन भारत की शिक्षा व्यवस्था मे लगातार एवं बार–बार हो रही विभिन्न दलों की राजनैतिक दखलदांजी के कारण शिक्षा नीति में आयी विसंगतियों के प्रति अपनी चिन्ता प्रकट करता है।

व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके नैतिक चरित्र एवं आचरण से निखरता है। विज्ञान एवं मनोविज्ञान सम्मन यह बात विश्वव्यापी स्वीकृति प्राप्त कर चुकी है कि शरीर, प्राण, मन, बुद्धि एवं आत्मा के सन्तुलित विकास के द्वारा मनुष्य के अन्तर्निहित गुणों के प्रगटीकरण हेतु मातृभाषा के माध्यम से योगाधारित शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है। NCERT ने यद्यपि योग के महत्व को समझकर उसे पाठ्यक्रम में समाहित किया है परन्तु उसे मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के नाते स्वीकृत कर इस विसंगति को दूर करने की पहल भी की जानी चाहिए।

समरस समाज ही संगठित एवं स्वावलंबी बन पाता है। सामाजिक समरसता में शिक्षा की भूमिका भी तब ही प्रभावी हो पायेगी जब समाज के सभी तबकों, जाति–पंथो, संप्रदायों, विभिन्न भाषा–भाषियों आदि के सभी स्त्री–पुरूषों को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध हो। शिक्षा के नाम पर व्यापार करने वाले एवं विदेशी निवेश के बल पर भारत की शिक्षा व्यवस्था में पैठ जमाने वाले व्यक्ति, संगठन तथा संस्थान समाज को अमीर एवं गरीब की शिक्षा के रूप में दो तबकों में बांट रही है। पांथिक अल्पसंख्यक होने का लाभ उठाकर शिक्षा में मनमानी कर अवांछित विषय भी पढाये जा रहे है। इन सब विसंगतियों को दूर कर शिक्षा सर्वसमावेशी एवं सर्वसुलभ हो ऐसी नीति बने। यह आज भी महती आवश्यकता है।

विश्व दरबार में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के दहलीज पर खड़ा भारत उस प्रतिष्ठा को तब ही प्राप्त कर पायेगा जब वह अपनी शिक्षा व्यवस्था को ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' की अवधारणा के अनुरूप ढाल ले। राजनैतिक उथल–पुथल एवं सत्ता के उलटफेर से प्रभावित होती रहें तो शिक्षा अपनी वह महती भूमिका निभा नहीं पायेगी। अतः स्वदेशी जागरण मंच का यह राष्ट्रीय सम्मेलन मांग करता है कि भारत के प्रबुद्धजन एवं भारत सरकार इन सुझावों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दें एवं उसे क्रियान्वित करने हेतु उचित व्यवस्था करें –

1. आठवीं कक्षा तक किसी छात्र को अनुत्तीर्ण न करने एवं दसवीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा को ऐच्छिक कर दिए जाने से शिक्षा में आ रही गिरावट को रोकने हेतु इस नियम को तत्काल प्रभाव से समाप्त करें।
2. सभी शासकीय एवं गैरशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में आधारिक रचना, छात्र–शिक्षक अनुपात तथा अन्य सभी सुविधा के डिजीटलाईज्ड नियमन को अनिवार्य कर शिक्षा व्यवस्था को अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से मुक्त करें।
3. स्वदेशी जीवन पद्धति, नैतिक शिक्षा अनुसंधान एवं सर्वसमावेशी पाठयक्रम, जिसमें तकनीकी शिक्षा, उद्योग पर शिक्षा कौशल विकास शामिल हो।
4. यह तभी सहज संभव हो पायेगा जब बार कांसिल या चार्टेर्ड एकांउटेंट संस्थान के भांति ग्राम सभा से लेकर सभी स्तरों पर शिक्षक एवं शिक्षाविदों के प्रतिनिधित्व के आधार पर स्वायत्त व स्वनियमनकारी 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' गठित हो तथा नीति निर्धारण से लेकर संचालन तक के सारे दायित्व निभाने का गुरूत्वपूर्ण कार्य उस आयोग को सौंप दिया जाए। ❑

ने बैठक में प्रतिभाग किया।

तीन दिसवीय सम्मेलन का उद्घाटन भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर हिन्दूस्तान एरोनोटिक लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन डॉ. रविन्द्र कुमार त्यागी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक श्री अरूण ओझा, संत महेश्वरानंद जी, राष्ट्रीय सह संयोजक श्री सरोज मित्र, डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा, प्रो. बी.एम. कुमार स्वामी, श्री आर सुन्दरम्, डॉ. अश्विनी महाजन, राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष उद्योगपति श्री पुरूषोतम हिसारिया, श्री लक्ष्मीनारायण भाला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख डॉ. मनमोहन वैद्य, दक्षिण मध्य क्षेत्र सह संगठन मंत्री श्री आर. सुन्दरम्, स्वदेशी जारगण मंच के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप', संघ चालक श्री ललित शर्मा आदि उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत स्वदेशी जागरण मंच राजस्थान प्रांत के संयोजक श्री भागीरथ चौधरी, प्रान्त सहसंयोजक श्री धर्मेन्द्र दुबे, डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी, व अन्य कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और राजस्थान का पारंपरिक साफा पहनाकर किया। राजस्थान संगीत अकादमी के कलाकारों मांड गायन 'पधारों म्हारें देश' के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया।

उद्घाटन सत्र में स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज ने प्रतिभागियों को स्वदेशी संस्कृति के सरंक्षण हेतु मार्मिक आह्वान करते हुए कहा कि भारत समूचे विश्वकी संस्कृति का पालना (झूला) है। उन्होंने बताया कि पूरे संसार में सभी देश अपनी मातृभाषा–स्वदेशी में ही व्यवहार करते है यद्यपि वे अंग्रेजी से परिचित होते है लेकिन हम भारतीय अंग्रेजी भाषा से अधिक मोहग्रस्त हो गये है। आज स्वदेशी भाषा को उपेक्षित

करने से ही आपसी कलह बढ रहा है। उन्होंने माता–पिता के लिए 'ममी' व 'पापा' जैसे प्रचलित संबोधनों की भर्त्सना करते हुए अधिकाधिक भारतीय संस्कृति परक शब्दावली प्रयोग की नेक सलाह दी। स्वामी महेश्वरानंद जी ने 'जीन्स' और 'सर' शब्दों की व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या द्वारा स्पष्ट किया कि हम विदेशी शब्दावली का प्रचलन बढाकर स्वदेशी प्रेम को बढावा नहीं दे सकेंगे। स्वामी जी ने ''जीन'' संबंधी वैज्ञानिक अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें हमारे कुल–वंश के गौरवपूर्ण संस्कारों के संरक्षण पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए।

अतिथियों ने स्वदेशी आंदोलन से जुड़े सृजनधर्मी, बुद्धिजीवियों द्वारा लिखित–संपादित पुस्तकों का लोकार्पण–विमोचन भी किया। इनमें प्रोफेसर भगवती प्रकाश (कुलपति, पैसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर) द्वारा लिखित तीन पुस्तकें – 1. सौर ऊर्जा : तकनीकी राष्ट्रवाद की प्रासंगिकता, 2. इकोनोमिक रिसर्जेन्स थ्रू मेड बाई इण्डिया, 3. आर्थिक सुधार एवं डॉ. अशोक शर्मा द्वारा लिखित ''गोधन दर्शन'' काशी प्रांत द्वारा प्रकाशित ''दीनदयाल उपाध्यायः प्रजातंत्र व ग्रामीण भारत'', डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा द्वारा लिखित ''भारत में ग्रामीण विकास'' शीर्षक पुस्तकें शामिल है।

भारत में रक्षा के क्षेत्र, नागरिक उड्डयन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एक. डी.आई) एवं सूचना तकनीकी (आईटी) एवं सूचना तकनीकी (आईटी) क्षेत्र में गहन अनुभव प्राप्त वैज्ञानिक हिन्दुस्थान एरोनोटिक लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन व उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. रविन्द्र कुमार त्यागी ने अद्यतन आंकड़ों एवं नवीनतम अनुसंधानों से प्राप्त निष्कर्षों के आलोक में में स्वतन्त्र भारत के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का प्रिज्मैटिक स्पैक्ट्रम प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि आने वाला एक दशक हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारी सुनियोजित

रणनीति हमें विश्व शक्ति बना सकती है वहीं पर असंगत सरकारी नीतियों से हमें और भी पिछड़ने की आंशका है।

डॉ. त्यागी ने बताया कि आज देश में 98 करोड़ मोबाइल काम आ रहे है। भारत में 30 करोड इंटरनेट यूजर्स में से 10 करोड लोग तो महज पिछले 18 महीनों में ही जुड़े है। इस तरह प्रचुर धन बाहर जाने लगा है। भारत में निर्मित उपकरणों के लिए ''मेक इन इण्डिया'' की बजाय कतिपय लोग केवल ''असेम्बलिंगइन इण्डिया'' का बिचौलियापन करके स्वदेशी अवधारणा को भ्रमित रूप में प्रस्तुत कर रहे है। उन्होंने इसके लिए खुद के सर्वर और ईमल आईडी विकसित करने का आह्वान किया।

उन्होंने बताया कि क्रूड ऑयल के भाव गिरने के दौर में यदि स्वदेशी कंपनियों को समुचित समर्थन दिया जाये तो वे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान पर ध्यान देकर अक्षुण्ण ऊर्जा की व्यवस्था कर सकेंगी। डॉ. त्यागी ने भारत में कमजोर नागरिक उड्डयन व्यवस्था की ओर संकेत करते हुए बताया कि भारत में भले ही 100 से ज्यादा हवाई अड्डे है। लेकिन आज भी 60 फीसदी यात्रीभार मात्र छह हवाई अड्डों पर ही है। अभी हमें 400 स्थानीय सुविधापरक क्षेत्रीय हवाई अड्डों की जरूरत है। आज भी हमारे उड्डयन विमानों की मरम्मत सिंगापुर में हो रही है क्योंकि वहां भारत की तुलना में सिर्फ 40 प्रतिशत खर्चा ही आता है।

उन्होंने भारत में हेलीकॉप्टर उद्योग की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चार साल पहले देश में 270 हेलीकॉप्टर थे अब घटकर 250 की रह गये है। अगले पांच वर्षों में भारत में लगभग बीस हजार करोड़ रूपये का नवीन क्षेत्र उभर सकता है।

भारतीय रक्षा विभाग का सलाना बजट 75 हजार करोड़ रूपये है अगले इस सालों में यह खर्च 13 लाख करोड़ रूपये तक बढ जायेगा। पिछले डेढ वर्षों में सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आयात सीमा 44 फीसदी तक निर्धारित कर दी थी जो अगले वर्ष सिर्फ 6 प्रतिशत ही रहेगी। अर्थात रक्षा सेवा संबंधी स्वदेशी कंपनियों के लिए सुनहरा दशक आने वाला है।

सिद्धांततः विदेशी कंपनियों भले ही तय प्रतिशत साझेदारी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करती है, लेकिन वे अपनी तकनीक कभी भी हमें हस्तान्तरित नहीं करती है। यही हालात सूचना तकनीकी एवं सिविल एविएशन्स क्षेत्रों में भी है।

देश में बढती जनसंख्या के अनुपात में बेरोजगार नौजावानों की संख्या बढकर 22 करोड़ हो चुकी है जिनका दंश 44 करोड़ माता–पिता झेल रहे है।

स्वदेशी जागरण मंच भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने के लिए पिछले 25 वर्षों से तत्पर है। मंच के माध्यम से जन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया प्रत्येक मंत्रालय

का अपना तकनीकी विशेषज्ञ समूह हो, प्रत्येक मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समूह में स्वदेशी जागरण मंच एवं अन्य संगठनों को प्रतिनिधित्व मिले। इसके अलावा 220 सार्वजनिक उपक्रमों को बीमार ईकाई या सफेद हाथी के रूप में बरकरार नहीं रखकर उनमें से लगभग 200 उपक्रमों को स्वदेशी कंपनियों में हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय सहसंयोजक श्री अरूण ओझा ने स्वदेशी जागरण मंच द्वारा देशभर के विभिन्न अंचलों में संपन्न गतिविधियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मंच ने गत वर्ष में भूमि अधिग्रहण विधेयक, सेज परियोजनाओं आंकड़े बताते है कि लंबित रही है। शेष 92 फीसदी परियोजनाऐं के लटके रहने के पीछे अन्यान्य कारण जिम्मेवार रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने अधिकांश ''सेज'' क्षेत्रों के लिए किसानों का हक छीन लिया और नई सरकार ने भी विकास के बहाने सख्त भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित करने का प्रयास किया। इसी प्रकार जीएम फूड को विदेशी पूंजी के बल पर थोपने के विरोध में मंच ने आंदोलन करके सफलता अर्जित की है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि बीटी कॉटन कपास के बारे में बढा चढाकर दावे किये जा रहे थे लेकिन सफेद मक्खियों के हमले के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जीएम तकनीकी का पर्दाफाश हुआ है। फिर भी अधिकांश लोग जीएम के भाड्यंत्र को समझ क्यूं नहीं रहे है?

हमारी उच्च शिक्षण संस्थाऐं मात्र व्हाइटकॉलर वाले प्रबंधक–कम– श्रमिक तैयार करके इतिश्री कर लेती है। डॉ. अब्दुल कलाम ने भी भारतीय पृष्ठभूमि पर खरी नहीं उतरने वाली शिक्षा प्रणाली को उचित नहीं माना था। प्रश्न यह कि आज हम एफ.डी.आई. के लिए क्यों मुंह ताक रहे है जबकि बैकों में 90 लाख करोड़ रूपये से अधिक जमा पड़े है। उद्घाटन सत्र में मंच संचालन उत्तर क्षेत्र के संगठक श्री सतीश कुमार जी ने किया। सम्मेलन के प्रथम सत्र में प्रांत संयोजकों ने अपने क्षेत्र में संचालित एवं संपन्न कार्यक्रमों का वृत प्रस्तुत किया।

आंध्र प्रदेश के श्री एम. कालिदास ने सुझाव रखा कि स्वदेशी तकनीक एक विज्ञान का सूचीकरण ;मदसपेजपदह ूवताद्ध होना चाहिये (उदाहरण के तौर पर लिज्जत पापड़ उद्योग के प्रबंधन को आदर्श मानते हुए।) उन्होंने बताया कि ठोस कचरे के पुनर्चक्रण की जरूरत है। उनकी संस्था ने बिजलीघर की राख से मजबूत ईंटे बनाने की तकनीक ईजाद की जिसके अनुसार भारत भर में 18000 से ज्यादा कुटीर उद्योग पनप चुके है, जिससे 54 हजार करोड़ रूपये का वार्षिक टर्नओवर है और दो लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह तकनीक उपजाऊ मिट्टी एवं महिलाश्रम को बचाती है तो साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ऐसी है कि कार्बन क्रेडिट कमाने पर भी आयकर चुकाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पंचायतें ऐसे ही स्वदेशी तकनीक को अपनाकर 100 वर्षों के लिए टिकाऊ सड़कें बना सकती है।

केरल प्रान्त के सह–संयोजक श्री थोडुपंरबल वर्गिज ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने व्यापक जनसमर्थन जुटाकर कोकाकोला एवं फार्मेसी कंपनियों के विरोध में एकजुटता दिखाई और लगभग दो लाख हैक्टेयर वनभूमि पर अतिक्रमण को रोकने में सफलता पाई है।

तमिलनाडू के संगठक श्री ई. कुमार संपत ने बताया कि तिरूचिरापल्ली में स्थानीय जिला प्रशासन एवं मिडिया ने भी पेप्सी कंपनी का समर्थन किया, लेकिन मंच ने तमिलभाषा में जागृति साहित्य प्रकाशित वितरित करके स्वदेशी अवधारणा को बुलंद किया है।

कर्नाटक के सह संगठक श्री एस. सी. पाटिल ने बताया कि मंच द्वारा समय–समय पर अनेक स्थानों पर स्थानीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर सार्थक चर्चा आयोजित की गई। कर्नाटक में 55 स्वदेशी भण्डार कार्यरत है।

डॉ. अशोक कुमार शर्मा ने स्वदेशी जागरण मंच को आंतरिक सुरक्षा कवच बताते हुए कहा कि स्वदेशी जागरण मंच वही काम कर रहा है जो काम सीमा पर सैनिक कर रहे है।

महाराष्ट्र से श्री अमोल पुसादकर ने बताया कि महाराष्ट्र के ग्रामांचल में स्वदेशी वस्तुओं के महत्व एवं स्वदेशी आन्दोलन की सफलता के बारे में क्षेत्रीय कार्यक्रम सुदूर गांवों में आयोजित किये गये।

गुजरात प्रान्त के संयोजक श्री रमेश दवे ने बताया कि विभिन्न अवसरों पर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा कार्यक्रम रखे गये। कार्यकर्ता स्वयं अपने परिजनों को कार्यक्रम में साथ लाते है ताकि परिवारजन भी इस आंदोलन को गंभीरता से समझ सकें। हमने दीपावली पर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम रखा

जिसके अनुकरण में अन्य क्षेत्रीय संगठनों ने भी ''चीनी माल के बहिष्कार'' का प्रचार किया।

मध्यप्रदेश डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा ने अफसोस जताया कि गत वर्ष में बाजार में 50 प्रतिशत चीनी पटाखों की तुलना में इस वर्ष 70 प्रतिशत चीनी पटाखें का इस्तेमाल किया गया है। मध्यप्रदेश में मंच द्वारा विविध प्रकोष्ठ भी खोले गये है यथा शिक्षक प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ, एनजीओ प्रकोष्ठ आदि।

राजस्थान प्रान्त के सहसंयोजक डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी ने बताया कि मेवाड़ में 13 प्रकार के धान–धान्यादि द्वारा ''ताराणी तेरस'' का आयोजन जन आन्दोलन का रूप लेता जा रहा है। जैव विविधता संरक्षरण की दृष्टि से यह अनुकरणीय कार्यक्रम है।

मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक प्रो. बी.एम. कुमारी स्वामी ने प्रथम प्रस्ताव 'सतत् विकास समय की मांग' का अंग्रेजी में तथा श्री संजीव माहेश्वरी ने हिन्दी में वाचन किया। तत्पश्चात् प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा ने अंग्रेजी में व श्री देवेन्द्र श्रीमानी ने प्रस्ताव क्रमांक 2 का वाचन किया। जिसका विषय 'मेड बाई इण्डिया' के स्थान पर शीर्षक ''मेड बाइ भारत'' (इण्डिया) रखा गया। श्री जे आर. जगदीश ने सत्र की अध्यक्षता की।

द्वितीय सत्र में शेष प्रांतों के पदाधिकारियों ने प्रांत–वृत की प्रस्तुति दी। डॉ. अश्विनी महाजन एवं श्री आर. सुन्दरम् ने विश्व व्यापार संगठन पर प्रस्ताव क्रमांक 3 का वाचन किया। श्री लक्ष्मीनारायण भाला ने शिक्षा में सुधार विषयक प्रस्ताव क्रमाक 4 का वाचन किया। श्री एस.सी. पाटिल ने प्रस्ताव का अंग्रेजी भावार्थ प्रस्तुत किया। प्रोफेसर भगवती प्रकाश ने ''वर्तमान आर्थिक परिदृश्य'' पर सारगर्भित विचार विश्लेषण प्रस्तुत किया।

तृतीय सत्र में प्रांतशः और क्षेत्रशः बैठकें आयोजित की गयी। जिनमें प्रांत

सम्मेलन, प्रांत स्तर पर विचार वर्ग तथा जनपद स्तर पर जिला सम्मेलन आयोजित करने के लिए तिथियों का निर्धारण पर चर्चा की गई।

सम्मेलन के दूसरे दिन तेलंगाना के श्री पी. श्रीनाथ, अरूणाचल प्रदेश के श्री कमलेश कुमार एवं उड़ीसा के श्री धीरेन्द्र नंदा ने प्रांत का वृत्त रखा और स्वदेशी की प्रांत में गतिविधियों को रेखांकित किया। इस सत्र में प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा द्वारा 'मेड बाय भारत' तथा स्वदेशी पत्रिका के अंग्रेजी संस्करण के संपादक श्री अजेय भारती द्वारा सतत विकास संबंधी प्रस्ताव रखा, जिसे ओउम् की ध्वनि के साथ पारित किया गया। 'प्रजातंत्र और ग्रामीण भारत' विषय पर काशी प्रांत में प्रवास के दौरान प्रोफेसर अशोक मडोक द्वारा दिए गए भाषणों के संकलन का विमोचन राष्ट्रीय संयोजक श्री अरूण ओझा ने किया। इस सत्र को संबोधित करते हुए स्वदेशी आंदोलन के वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय सहसंयोजक श्री सरोज मित्र ने कहा कि हमारे मन और मस्तिष्क में अखण्ड भारत की परिकल्पना हमेशा बनी रहनी चाहिए। उत्तर क्षेत्र के संगठक श्री सतीश कुमार ने कहा कि सौर उर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए देशी पूंजी का बाहर जाने से रोकने के लिए स्वदेशी मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सौर उर्जा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने सौर उर्जा के लिए केंद्र सरकार द्वारा विश्व स्तर पर फोरम बनाने के निर्णय का भी स्वागत किया। राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी ने 'जैव संवर्धित फसलें' (जीएम करोप) विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि जब यूरोपीय देश जीएम के दुष्प्रभावों को देखते हुए उससे किनारा कर रहे हैं तो हमारे देश की सरकार परीक्षण और उत्पादन की अनुमति देने के लिए उतावली है।

महिला, आर्थिक, देशी चिकित्सा तथा कृषि विषय पर समानांतर सत्र आयोजित किए गए। सामानांतर सत्रों में विविध प्रांतों से आये प्रतिनिधियों ने विशेषज्ञों से प्रश्न किए और संबंधित विषयों पर अपने सुझाव दिए। समानांतर सत्र के पश्चात् स्वदेशी संदेश यात्रा निकाली गई। स्वदेशी संदेश यात्रा महाराजा उम्मेद सिंह स्टेडियम से प्रांरभ होकर मुख्य सड़क और बाजार होते हुए सरकारपुरा स्थित गोकुल धाम मैदान (गांधी मैदान) तक पहुंची। यात्रा में विभिन्न प्रांतों के हजारों कार्यकर्ता बैनर, झंडे और नारे लिखी हुई तख्तियां लेकर चल रहे थे तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बहिष्कार और जन–जन से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील संबंधी नारे लगा रहे थे। स्वदेशी कार्यकर्ताओं का संदेश यात्रा के दौरान जोधपुर के आम नागरिकों एवं विभिन्न संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा के दौरान बज रहे ढोल नगाड़े और गूंज रहे नारों से पूरा जोधपुर

महानगर स्वदेशीमय हो गया।

स्वदेशी संदेश यात्रा के समापन पर गांधी मैदान में आयोजित विशाल हुंकार सभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय संयोजक श्री अरूण ओझा ने लोगों का आह्वान किया कि वह अपने जीवन का कुछ समय निकालकर इस धर्मयुद्ध में शामिल हों। उन्होंने कहा कि मंच का सपना है–शोषण और विषमता से मुक्त भारत बने। उन्होंने कहा भारतवर्ष सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं, विशिष्टता का सूचक है। यह नीयती की आकांक्षा और सपना है कि भारत फिर से दुनिया में अपना सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित करे। उन्होंने कहा कि सात दशकों की स्वतंत्रता के बाद भी भारत दुनियां का एक बड़ा कर्जदार देश बन गया है। इसके लिए नेहरू की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जिस व्यक्ति के हाथों में सत्ता सौंपी गयी वह यहां की मिट्टी में पला–बढ़ा नहीं था और यहां की जनता को निरक्षर, मूर्ख और हिंसक मानता था। उसने विकास का जो रास्ता चुना उससे आज देश का गांव उजड़ रहा है, खेती उजड़ रही है।

राष्ट्रीय सह संयोजक प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने चीन को निशाना बनाते हुए कहा कि चीन निर्मित वस्तुएं खरीदना देश के सैनिकों की विधवाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस देश में उत्पादन के साधनों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा होता जा रहा है। देशी गायों के अस्तित्व पर छाये संकट के प्रति भी उन्होंने सचेत किया।

राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने कश्मीर और चैन्नई की प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रकृति के साथ छेड़–छाड का खामियाजा हमें इसी रूप में झेलना पडेगा। उन्होंने अनियंत्रित विकास पर सवाल खड़े किए। नागपुर की प्रांत महिला प्रमुख श्रीमति अमिता पत्की ने भी सभा को संबोधित किया। अतिथियों का स्वागत राजस्थान प्रांत संयोजक श्री भगीरथ चौधरी और संचालन प्रांत सहसंयोजक श्री धर्मेन्द्र दुबे ने किया।

12वें राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे और अंतिम दिन पहले सत्र में शिक्षा और विश्व व्यापार संगठन पर प्रस्तुत प्रस्ताव को ओउम की ध्वनि के साथ पारित किया गया। इस सत्र में चीन से चुनौतियां विषय पर वक्तव्य रखते हुए कहा कि मुंबई हमले का असली गुनाहगार जकीउररहमान लखवी को यू.एन.ओ. में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव का जिस चीन ने विरोध किया आज उससे हम 60 अरब डॉलर का आयात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन भारत से लौह अयस्क सहित कच्चे माल को आयात करता है तथा निर्मित वस्तुओं से भारत के बाजाार को पाटता चला जा रहा है। अमरीका जैसा देश चीन पर 238 प्रतिशत एंटी डंपिंग शुल्क लगाता है, जबकि हम अकारण चीन को आर्थिक उपहार दिए चले जा रहे हैं। इस सत्र में मंच पर श्री आर.सुन्दरम, श्री अजेय भारती व श्री धर्मेन्द्र भदौरिया आदि उपस्थित थे। अध्यक्षता मध्य क्षेत्र के संयोजक श्री जगत नारायण सिंह व संचालन उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल के सह संयोजक श्री यशोवर्द्धन त्रिपाठी ने किया।

तीसरे दिन के द्वितीय सत्र में राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने संगठनात्मक मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की और व्यवस्थाओं व आंदोलन को लेकर उनकी प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए। आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे। अखिल भारतीय विचार मंडल प्रमुख श्री अजय पत्की ने विचार वलय आयोजित करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' ने स्वदेशी आंदोलन को गति देने के लिए मीडिया की भागीदारी पर बल दिया।

तीन दिसवीय 12वें राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन समापन सत्र में मंच के अखिल भारतीय संयोजक श्री अरूण ओझा, सहसंयोजक श्री सरोज मित्र, प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी, श्री आर. सुन्दरम, डॉ. अश्वनी महाजन, पं. दीन दयाल शोध संस्थान के डॉ. महेशचन्द्र शर्मा, श्री जे.आर. जगदीश, डॉ. रणजीत सिंह, श्रीमति रेणु पुराणिक, श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' श्री सतीश कुमार, श्री अतुल भंसाली, श्री भगीरथ चौधरी उपस्थित थे। श्री अरूण ओझा ने प्रकाश माली द्वारा गाये गीत 'बने राष्ट्र का धर्म स्वदेशी' तथा स्वदेशी पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का लोकार्पण किया।

समापन भाषण में श्री अरूण ओझा ने कहा कि सम्मेलन 'प्रकाश दीप' की भांति है, जो आगे तक रोशनी दिखाता रहेगा। उन्होंने राष्ट्रीय और प्रांत स्तर

पर नये पदाधिकारियों के दायित्व की घोषणा की–

अखिल भारतीय

1. श्री सतीश कुमार– अखिल भारतीय सह–विचार मंडल प्रमुख (अतिरिक्त दायित्व)
2. डॉ. निरंजन सिंह– अखिल भारतीय सहप्रचार प्रमुख
3. श्री संजीव महेश्वरी– अखिल भारतीय सहकोष प्रमुख एवं क्षेत्रीय संयोजक
4. श्री भगीरथ चौधरी'– अखिल भारतीय प्रमुख (कृषि प्रकोष्ठ)

क्षेत्रीय

1. श्री धर्मेन्द्र भदौरिया– क्षेत्रीय विचार मंडल प्रमुख
2. श्री मनोज द्विवेदी– क्षेत्रीय सह संपर्क प्रमुख
3. श्री बलराम नंदवानी– क्षेत्रीय सहसंयोजक
4. श्री गोविन्दराम अग्रवाल– क्षेत्रीय विचार मंडल प्रमुख (उत्तर क्षेत्र)ञ
5. श्री महादैव्वया–सह क्षेत्र संयोजक (कर्नाटक, आं.प्र., तेलंगाना)

राज्य

1. **कर्नाटक**– 1. श्री एस.सी. पाटिल–प्रांत सह संयोजक, 2. श्री एन.आर. मंजुनाथ–प्रांत सहसंयोजक,
2. **आंध्र प्रदेश**– 1. श्री जनार्धन (सीए)–प्रांत संयोजक, 2. श्री कृष्ण भगवान–प्रांत संगठक
3. **मध्य प्रदेश**– 1. श्री अरूषेन्द्र कुमार–प्रांत सहसंयोजक, 2. श्री सुरेश बिजौलिया–प्रांत सहसंयोजक (मालवा)
4. **हिमाचल प्रदेश**– 1. श्री ललित कौशल–प्रांत सहसंयोजक, 2. श्री जनकराज मुदगिल–प्रांत कार्यसमिति सदस्य
5. **पंजाब**– श्री दिनकर पराशर–प्रांत सहसंयोजक

6. **हरियाणा**– 1. श्री विजय वत्स–प्रांत संयोजक, 2. सतेन्द्र सरौत–प्रांत सहसंयोजक,
7. **अवध**– डॉ. रेखा शर्मा–प्रांत महिला प्रमुख
8. **काशी**– 1. श्री सर्वेश पांडेय–प्रांत संयोजक, 2. श्री विजय कुमार सिंह–प्रांत सहसंयोजक
9. **राजस्थान**– 1. श्री राजकुमार चतुर्वेदी–आंचलित विचार मंडल प्रमुख (राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र), 2. श्री भगवती लाल जगोठिया–प्रांत सहसंयोजक, 3. श्री धर्मेन्द्र दुबे–प्रांत संयोजक, 4. श्री शंकरलाल–प्रांत सहसंयोजक
10. **दिल्ली**– 1. सुशील पांचाल–प्रांत संयोजक, 2. श्री कमल तिवारी–प्रांत सहसंयोजक, 3. श्री रविन्द्र सोलंकी–प्रांत सहसंयोजक, 4. श्री विकास चौधरी–दिल्ली, हरियाणा संघर्ष वाहिनी प्रमुख

राष्ट्रीय परिषद सदस्य

1. पंजाब– श्री गौरव टंडन, श्री जगमोहन सिंह, श्री मदनलाल, डॉ. राकेश शर्मा, श्री रणवीर कुमार, श्रीमति सुशीला देवी, **2. जम्मू कश्मीर**– श्री विपिन उपाध्याय, श्री चरण देव सिंह जमवाल, **3. हिमाचल प्रदेश**– श्री ओंकार सिंह जयसवाल, श्री इंद्र ठाकुर, **4. बिहार**– श्री यदुनानंद प्रसाद, **5. उड़ीसा**– श्री अभय सामंत राय, श्री हिमांशु चौलिया, **6. मध्य प्रदेश**– श्री श्रीराम गोयल, **7. उत्तर प्रदेश (पं.)**– श्री अमिलेश अमित, श्री सर्वेश वाजपेयी।

चिकित्सा के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दुष्चक्र का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि मुक्त बाजारवाद के नाम पर दुनिया में शोषण और अत्याचार हो रहा है जिसका स्वदेशी जागरण मंच प्रबल विरोध करेगा। आर्थिक सुधार के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन और वितरण का जो परंपरागत स्वदेशी विकेन्द्रित ढांचा है उसे बर्बाद किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि दुनिया के गरीब देशों का शोषण हो रहा है। गरीब देश और गरीब तथा अमीर देश और अमीर होते जा रहे हैं। विदेशी पूंजी के नाम पर देश में हौवा खड़ा किया जा रहा है कि बगैर विदेशी पूंजी के देश का विकास रूक जायेगा। उन्होंने कहा कि हमें एक नई राह तलाशनी होगी, एक नये स्वर की आवश्यकता है। देश के बुद्विजीवियों, अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों को सोचना होगा। उन्होंने कहा कि गांधी, अंबेडकर, पं. दीन दयाल उपाध्याय और राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी के सपनों में जो भारत की तस्वीर थी, स्वदेशी जागरण मंच को आज उसे साकार करना होगा।

उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को यह नहीं समझना चाहिए कि दुनिया और देश जिस राह पर जा रहा है उसे हम अकेले कैसे रोक सकते हैं? उन्होंने चर्चिल की एक पंक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि दुनियां आपके विषय में चाहे जो भी सोचे हमें अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते रहना चाहिए। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ते हुए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि हम आगे बढ़े और परिवर्तन का सूत्रधार बनें। समापन पर राजस्थान प्रांत की ओर से केंद्रीय पदाधिकारियों को साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ मंच के 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो गया। ❑❑

दवाईयों के पेटेंट पर केन्द्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य

देश में स्वास्थ्य–रक्षा व चिकित्सा लागतों पर नियंत्रण और वैश्विक मानवता के प्रति संवेदनावश ही विगत कई वर्षों से चल रहे अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और ओबामा प्रशासन के दबाव को पूरी तरह से नकारते हुए अब तो सरकार ने दिसंबर २९, २०१५ को व्यक्त रूप से ही इन मुद्दों पर अमरीकी दबाव में आने से सर्वथा इंकार कर दिया है।
– प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

केन्द्र सरकार द्वारा अमेरिकी दबाव की अनदेखी कर दवाईयों के पेटेंट के मामले में अनिवार्य अनुज्ञापन (कम्पल्सरी लाईसेसिंग) के प्रावधानों एवं भारतीय पेटेन्ट अधिनियम की धारा 3 डी में, किसी भी प्रकार की शिथिलता लाने से इन्कार कर देने का निर्णय अत्यंत स्वागत योग्य है। भारत आज 'फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड' कहलाता है और पेटेंट के क्षेत्र में उपरोक्त दोनों मानवोचित प्रावधानों के कारण ही आज विश्व भर में ब्लड केंसर, एच.आई. वी एड्स और अन्य गंभीर बीमारियों के सस्ते ईलाज के लिए सस्ती दरों पर दवाईयाँ सुलभ करा पा रहा है, जिसके फलस्वरूप ही आज विश्व के 40 प्रतिशत से भी अधिक रोगी अपना ईलाज भारत में सस्ती दर पर सुलभ दवाईयों के कारण ही करा पा रहे है। देश में स्वास्थ्य–रक्षा व चिकित्सा लागतों पर नियंत्रण और वैश्विक मानवता के प्रति संवेदनावश ही विगत कई वर्षों से चल रहे अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और ओबामा प्रशासन के दबाव को पूरी तरह से नकारते हुए अब तो सरकार ने दिसंबर 29, 2015 को व्यक्त रूप से ही इन मुद्दों पर अमरीकी दबाव में आने से सर्वथा इंकार कर दिया है। पिछली सरकार इन मुद्दों को व्यक्त रूप से नकारने का साहस नहीं दिखा पायी थी। इस संबंध में विश्व व्यापार संगठन के हाल ही में नैरोबी में सम्पन्न दसवें मंत्रीय स्तरीय सम्मेलन में भी भारत ने विकासशील व अल्पतम विकसित देशों के पक्ष को मजबूती से रखते हुए इन मुद्दों पर पर्याप्त दृढ़ता दिखाई थी।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में जब भारत के तत्कालीन चीफ कन्ट्रोलर ऑफ पेटेन्ट्स, पी.एच. कुरियन ने जर्मन कम्पनी 'बायर एजी' की 2,80,000 रूपये कीमत

वाली, लीवर व किडनी केंसर की 'नेक्सावर' नामक दवाई को भारत को 8,800 रूपये में बनाकर बेचने के नेटको नामक भारतीय कंपनी को कम्पलसरी लाईसेंस दे दिया था, तब केन्द्र सरकार ऐसा साहस नहीं दिखला पायी थी। वस्तुतः श्री कुरिअन द्वारा दिये लाइसेंस के विरूद्ध तब तत्कालीन मनमोहसिंह सरकार पर इस कम्पल्सरी लाइसेंस के विरूद्ध आए यूरो अमेरीकी दबाव को वह सहन नहीं कर पाई थी। इसलिए इस बायर एजी कंपनी द्वारा 2 लाख 80 हजार रूपये में बेचे जा रहे लीवर व किडनी केंसर के इस इन्जेक्शन को 8800 रूपये में बनाकर बेचने का कम्पल्सरी लाइसेंस देने वाले चीफ कंट्रोलर ऑफ पेटेन्ट्स, पी.एच. कुरियन का कार्यकाल 2.5 वर्ष शेष होने पर भी सरकार उनका इस पद से स्थानांतरण कर देने के दबाव में आ गई थी। मानवता के हित में देश के विद्यमान कानून और 2001 के बहुपक्षीय दोहा घोषणा पत्र के अनुरूप ही कम्पल्सरी लाइसेंस देने पर भी पी.एच. कुरियन को समय से पहले उस पद से हटा दिया देने अत्यंत हास्यास्पद निर्णय था। उसके बाद कोई भी चीफ कंट्रोलर ऑफ पेटेंट देश में कम्पल्सरी लाइसेंस देने का साहस नहीं जुटा पाया है।

इतना करने अर्थात कुरियन को पद से हटा देने के बाद भी तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के विरूद्ध अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने दण्डात्मक कार्यवाही तक के लिए भारत के विरूद्ध आऊट ऑफ साइकिल जन सुनवाई प्रारंभ कर दी थी। तब यह लग ही रहा था कि अमेरिकी प्रसासन भारत के विरूद्ध अमेरिकी कानून सुपर 301 के अधीन कार्यवाही करने के लिए भारत को प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री की श्रेणी में रखने वाला है। लेकिन लोकसभा चुनावों के बीच अप्रेल 30, 2013 को जारी अपने प्रतिवेदन में उसने ऐसा नहीं किया।

भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा ३ डी के कारण ही ब्लड कैंसर की दवा ग्लिवेक आज भी देश में रू. १२०० के स्थान पर मात्र रू. ९० में उपलब्ध है। अतएव् पेटेंट व ट्रिप्स के मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार की दृढ़ता लाखों रोगियों के लिये जीवनदान तुल्य निर्णय है।

अब तो वर्तमान सरकार की दृढ़ता को देखते हुए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि माइकल फ्रोमेन ने किसी आऊट ऑफ साइकिल समीक्षा जैसा कदम दुबारा नहीं उठाया है जबकि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने अपनी ताजा वार्षिक स्पेशल 301 रिपोर्ट में इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

इस संबंध में भारत सरकार अपनी दृढ़ता बनाये रखते हुए अन्य भी विदेशी पेटेंट युक्त महंगी जीवन रक्षक दवाईयों के संबंध में भी उदारतापूर्वक कम्पल्सरी लाइसेंस जारी करने की नीति पर आगे बढ़े तो देश व विदेश के आम रोगियों के लिए वरदान सिद्ध होगा। अच्छा तो यही होगा कि सरकार पेटेंट के अधीन आने वाली अन्य भी ऐसी महंगी दवाईयाँ, जिन्हें कोई भी स्थानीय उत्पादक उसके विदेशी पेटेंटधारी की तुलना में एक चौथाई से कम कीमत पर बनाकर बेचने को प्रस्तुत हो जाये उन सभी के लिए स्वतः अनिवार्य अनुज्ञापन (ऑटोमेटिक कम्पल्सरी लाइसेंस) का प्रावधान करे।

ऐसी अनेक दवाईयां है यथा रोष कंपनी की केंसर–रोधी 1,35,200 रूपये की दवा, हरसेप्टीन मर्क कंपनी की अरबीटक्स जो 87,920 रूपये की है, ब्रिस्टोल मेयर स्क्विब की आई जेम्प्रा जो 66,460 रू. की है, फाइजर कंपनी की मेकुजन जो 45,350 रूपये की है और सनोफी एवेंटीस की फास्चरटेक 45,000 रूपये की कीमत पर उपलब्ध है। ऐसी सभी महंगी दवाईयों के लिए भी कम्पल्सरी लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए। इनमें से अधिकांश दवाईयां केंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं अन्य गंभीर वेदनाओं के लिए प्रभावी दवाईयां हैं।

ऐसे सभी मामलों में ऐसा कम्पल्सरी लाइसेन्स आवश्यक है। इसी प्रकार भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3 डी के कारण ही ब्लड कैंसर की दवा ग्लिवेक आज भी देश में रू. 1200 के स्थान पर मात्र रू. 90 में उपलब्ध है। अतएव् पेटेंट व ट्रिप्स के मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार की दृढ़ता भारत व विश्व भर के मध्यम व निम्न आय वर्ग के लाखों रोगियों के लिये जीवनदान तुल्य निर्णय है। ❑❑

नैरोबी सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गैर बराबरी की लड़ाई

दिसंबर 15 से 18 के बीच विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की वार्तायें केन्या की राजधानी नेरोबी में होनी निश्चित थी, जो एक और दिन आगे बढ़ा दी गई और अंतिम घोषणा 19 दिसंबर को ही तैयार हो सकी। रात दिन चलने वाली बातचीत और बहस के हालांकि कड़े परिश्रम के बाद भारत का प्रतिनिधि मंडल अंतिम घोषणा में यह बात शामिल करवा सकने में सफल हुआ कि आयातों की बाढ़ को रोकने के लिए आयात शुल्कों के रूप में विशेष बचाव उपाय (एसएसएम) अपनाना विकासशील देशों का अधिकार है और यह बात भी सार्वजनिक भंडारण और खाद्य सुरक्षा हेतु स्थायी समाधान होने तक विकसित देश भारत और अन्य मुल्कों की सरकारों द्वारा किसानों से अनाज की सरकारी खरीद पर कोई विवाद नहीं लायेंगे। लेकिन सम्मेलन के समापन सत्र से बाहर आने से पहले अपनी ट्वीट में जब वाणिज्य मंत्री ने यह कहा कि इस बात से अत्यंत निराश हैं कि 'दोहा विकास चक्र' को आगे बढ़ाने पर मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में सफलता नहीं मिल पाई, तो यह बात स्पष्ट हो गई कि विकसित देश किसी भी हालत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकासशील देशों की समस्याओं को समझ कर उसका समाधान नहीं देना चाहते।

रात दिन चलने वाली बातचीत और बहस के कड़े परिश्रम के बाद भारत का प्रतिनिधि मंडल अंतिम घोषणा में यह बात शामिल करवा सकने में सफल हुआ कि आयातों की बाढ़ को रोकने के लिए आयात शुल्कों के रूप में विशेष बचाव उपाय (एसएसएम) अपनाना विकासशील देशों का अधिकार है।
– डॉ. अश्वनी महाजन

सम्मेलन के बाहर विभिन्न देशों के संगठनों द्वारा जो प्रदर्शन हो रहे थे, उन संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों जो चर्चा चल रही थी और दुनिया भर के मीडिया में जो चर्चा चल रही थी, यदि उसे संक्षेप में कहा जाये तो कहेंगे कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना हेतु मराकेश मे हुए समझौते से उत्पन्न मुद्दों के कारण विकासशील देशों को जिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, उसके निराकरण के लिए विश्व व्यापार संगठन के दोहा (कतर) में आयोजित चौथे मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में जो बात तय हुई थी कि उन मुद्दों पर पहले चर्चा होगी और उसके बाद डल्ब्यूटीओ में आगे बात बढ़ेगी। इस सहमति को दोहा विकास चक्र कहा गया था, उस पर चूंकि विकसित देश आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है और वे उस चक्र को मझधार में ही छोड़कर नये मुद्दों पर चर्चा शुरू करना चाहते हैं, इसलिए गरीब मुल्कों को अपने हितों के संरक्षण के लिए विश्व व्यापार संगठन में जूझना पड़ रहा है।

लेकिन किसी भी मुद्दे पर विकसित देश समाधान नहीं देना चाहते थे। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि भारत का किसान सही कीमत न मिलने के कारण आत्म हत्या कर रहा है। जबकि भुखमरी से पीड़ित दुनिया के 25 प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं और उनकी खाद्य सुरक्षा के लिए भारत सरकार जो प्रयास कर रही है, उस पर उनकी आपत्ति है। भारत सरकार जो आयातों की बाढ़ रोकने के लिए पहले से ही विशेष बचाव उपाय (एसएसएम) अपनाने के रूप में पहले से ही उपलब्ध अधिकार पर समाधान चाहती थी, उस पर भी वे

सहमति देने के लिए तैयार नहीं थे। जिस पर वे चाहते थे कि उन्हें भारत को अपने कृषि उत्पादों के निर्बाध निर्यातों की अनुमति मिल जाए। इसके साथ ही साथ वे भारत से होने वाले निर्यातों पर श्रम मानक और पर्यावरण मानक तो लादना चाहते ही थे, साथ ही साथ वे ई–कॉमर्स को भी व्यापार वार्ताओं के अंतर्गत शामिल करना चाहते थे।

विवादों से भरा है डब्ल्यूटीओ का इतिहास

भारत समेत 162 देशों की सदस्यता वाले डब्ल्यूटीओ का लंबा इतिहास है। 1995 से पहले विश्व व्यापार 'गैट' यानि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ द्वारा संचालित होता था। हालांकि डब्ल्यूटीओ के समर्थकों का कहना है कि इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कड़े नियमों के आधार पर चलाया जाना संभव हुआ है। उनका कहना है कि देशों को नियमों में बांधकर टेरिफ और नॉन टेरिफ बाधाओं को कम करते हुए व्यापार में वृद्धि संभव होती है।

लेकिन इसके आलोचकों का कहना है कि न केवल विश्व व्यापार संगठन के बनने के समय हुआ मराकेश समझौता विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर दबाव डालकर उनके हितों के विपरीत करवाया गया, जिसमें कृषि, निवेश, पेटेंट और सेवाओं जैसे विषयों को शामिल करते हुए विकासशील देशों के शोषण का तंत्र बनाया गया। 'ट्रिप्स' के नाम पर बाध्यकारी समझौता करते हुए, भारत और अन्य देशों को अपना पेटेंट कानून बदलने के लिए बाध्य किया गया ताकि अमरीका और अन्य विकासशील देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनिओं के पेटेंट अधिकारों के बदले में उन्हें ज्यादा से ज्यादा रायल्टी मिल सके।

डब्ल्यू.टी.ओ. की स्थापना के समय, पेटेंट कानून में बदलाव दवाईयां महंगी होगी जिसके कारण भारत के जनस्वास्थ्य

विकासशील देशों के हितों के संरक्षण के लिए जरूरी है कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों में आमूलचूल बदलाव लाया जाए।

पर प्रभाव पड़ेगा, यह बात सिद्ध होने पर, डब्ल्यू.टी.ओ. समर्थकों का कहना था कि व्यापार वार्ताओं में लेनदेन होता ही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है। यदि कृषि में मुक्त व्यापार होता है तो हमारे किसान को लाभ होगा। हमारा किसान दुनिया के बाजार में अपना सामान बिना रूकावट बेच पाएगा। यह भी कहा गया कि सब्सिडी पर समझौते के कारण विकसित देशों को कृषि पर अपनी सब्सिडी समाप्त करना पड़ेगा और इस कारण हमारी कृषि लागत कम होने के कारण हमारे किसान की प्रतिस्पर्द्धा शक्ति कहीं ज्यादा होगी और हमारा किसान अमीर हो जाएगा।

खेती और किसान की बदहाली

लेकिन जब से डब्ल्यू.टी.ओ. आस्तित्व में आया है, हमारा किसान खुशहाल होना तो दूर बदहाल ही हुआ है। जो कहा गया था कि हमारे किसान के फूल, फल, सब्जियां और अनाज विकसित देशों में बिकेगा; वो तो हुआ नहीं लेकिन विकसित देशों से फल, फूल और अनाज भारत में आने लगे। मराकेश समझौते के मुताबित विकसित देशों द्वारा कृषि को दी जाने वाली अपनी सब्सिडी घटानी थी, उसके बजाय उन्होंने सब्सिडी बढ़ा दी। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक तरकीब पहले से ही निकाल ली थी। हुआ यह कि उन्होंने अपनी अधिकांश सब्सिडी को 'ग्रीन बाक्स' में डाल दिया जिसे घटाने की कोई बाध्यता नहीं ।

विकसित देशों ने स्वयं तो अपनी सब्सिडी को घटाया नहीं, जबकि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून को अंजाम देने के लिए किसानों से सीधा अनाज की खरीद बढ़ाई तो उसपर आपत्ति जरूर कर दी कि भारत कुल उत्पादन पर दस प्रतिशत सब्सिडी की सीमा को लांघ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रारंभिक समझौते में नियम ऐसे बनाए गए थे कि सब्सिडी की माप करने के लिए आधार वर्ष 1986–88 रखा गया था यानि यदि उस समय गेहूं की कीमत यदि 385 रूपए प्रति क्विंटल थी और आज भारत सरकार 1400 रूपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद कर रही है तो 1015 रूपए की सब्सिडी मानी जाएगी। उधर भारतीय किसान को विदेशों से कृषि वस्तुओं की बाढ़ से जुझना पड़ रहा है, क्योंकि भारी सब्सिडी वाले विदेशी कृषि उत्पादों के आयातों के कारण उसे अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता।

ऐसे में जब भारत सरकार डब्ल्यूटीओ में समाधान चाहती है, तो उसे न केवल भारी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बल्कि श्रम एवं पर्यावरण मानकों के रूप ऐसी बातें भी मनवाने का प्रयास हो रहा है, जिससे आने वाले समय में उसे और परेशानियां उठानी पड़ेगी। ऐसे में प्रश्न उठता है कि भारत और अन्य विकासशील देशों ने विश्व व्यापार संगठन में बहुपक्षीय व्यापार समझौता करके अपने लिए मुसीबत तो नहीं खड़ी कर ली है। विकासशील देशों को सोचना पड़ेगा कि वे विकसित देशों द्वारा बुने गए विश्व व्यापार संगठन के नियमों के जाल से कैसे निजात पाएं। विकासशील देशों के हितों के संरक्षण के लिए जरूरी है कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों में आमूलचूक बदलाव लाया जाए, ताकि इन देशों की कृषि, उद्योग और व्यापार की ठीक प्रकार से रक्षा हो सके। ❑❑

कृषि मसले सुलझाने में नैरोबी भी हुआ फेल

विश्व व्यापार संगठन के दसवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नैरोबी में विकसित एवं विकासशील देशों को जीत व हार दोनों के ही स्वाद चखा गया। विकसित देश कृषि निर्यात पर आर्थिक सहायता को खत्म करवाकर दोहा सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सहमति बनवाने में सफल रहे। वास्तव में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक राबर्ट अजेवेडो ने स्वयं माना कि मीडिया इस सम्मेलन को एक असफलता के रूप में प्रचारित करेगा, लेकिन अधिकतर किसान संगठन इस सम्मेलन को विकासशील देशो के किसानों के लिए अहितकारी मान रहे हैं।

नैरोबी सम्मेलन में कृषि निर्यात पर आर्थिक सहायता को खत्म करने को लेकर जो सहमति बनी उसका मुख्य कारण चीन व ब्राजील का अंतिम समय में अमेरिका व यूरोपीयन यूनियन के साथ मिल जाना रहा। दुनिया के संपंन देश विशेष सुरक्षा प्रावधान, न्यूनतम सर्मथन कीमत, कृषि निर्यात पर आर्थिक सहायता जैसे मुददों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने पर दोहा सम्मेलन से ही लगातार जोर देते रहे है। अब कहीं जाकर उपरोक्त में से एक विषय पर विराम लगा है। नैरोबी में विकासशील देश हांगकांग मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से जारी विशेष सुरक्षा प्रावधानों को जारी रखने पर कामयाब रहें। ऐसा होने से विकासशील देश, विकसित देशों से कृषि पदार्थो के आयातों के बहुत अधिक बढने व उसकी वजह से देश में कृषि पदार्थो की कीमते बहुत अधिक कम होने से अस्थायी रूप से आयातित कृषि पदार्थों पर सीमा शुल्क बढाने की अनुमति अब भी जारी रहेगी।

दुनिया के संपंन देश विशेष सुरक्षा प्रावधान, न्यूनतम सर्मथन कीमत, कषि निर्यात पर आर्थिक सहायता जैसे मुददों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने पर दोहा सम्मेलन से ही लगातार जोर देते रहे है। अब कहीं जाकर एक विषय पर विराम लगा है।
– रणवीर सिंह

दूसरा मुख्य विवादित विषय विकासशील देशों द्वारा आगत (खाद, बीज, कीटनाशक, सिंचाई आदि) व निर्गत (न्यूनतम समर्थत कीमत) पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता है। विकसित देश, विकासशील देशों द्वारा किसानों को दी जाने वाली खाद, बीज, कीटनाशक, सिंचाई आदि पर आर्थिक सहायता में फसलों के लिए दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थत कीमत को भी जोड़ देते है जो वास्तव में निर्धारित 10 फीसदी आर्थिक सहायता के स्तर से उपर निकल जाती है। विकसित देश हर हाल में विकासशील देशों का बाजार अपने लिए खुलवाना चाहता है इसलिए विकसित देश हर सम्मेलन में विकासशील देशों में आर्थिक सहायता को चरणबद्ध तरीके से खत्म करवाना चाहता है जिसका भारत समेत सभी विकासशील देश विरोध करते रहे। भारत के विरोध को सही मान लिया गया जिस कारण से इस बार भी

आगत व निर्गत आर्थिक सहायता अब भी पूर्ववत जारी रहेगी। भारत का भी यहीं पक्ष रहा कि विश्व के सबसे अधिक भूखमरी के शिकार लोगो के लिए भारत में चलाये जा रहें खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए अनाज की कीमतों को कम रखना अतिआवश्यक है जिसके लिए अनाज की लागत को कम रखने के लिए आर्थिक सहायता को जारी रखना भी अतिआवश्यक है।

विश्व व्यापार संगठन में औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात पर आर्थिक सहायता 50 वर्ष पहले ही बंद कर दी गई थी, लकिन विश्व व्यापार संगठन के दसवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नैरोबी में यही नियम अब कृषि पदार्थो पर लागू कर दिया गया है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं।जैसे वर्तमान में चीनी का अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में मूल्य 20 रूपये प्रति किलो है जबकि हमारे देश में इसका मूल्य 30 रूपये प्रति किलो है देश में चीनी की अधिकता होने पर इसका निर्यात किया जाऐगा तथा निर्यातक को उसके प्रति किलो के घाटे को सरकार निर्यात पर आर्थिक सहायता देकर पूरा करती है। इसका एक फायदा तो ये रहता है कि देश में पैदा आधिक्य उत्पादन विदेशी मुद्रा अर्जित करता है व दूसरा फायदा यह होता है कि किसानों को मिलने वाली फसल की किमत कम होने से बच जाती है। लेकिन अब नैरोबी सम्मेलन के बाद कृषि पदार्थो के निर्यात पर आर्थिक सहायता बंद कर दी जाऐगी जिससे अब अतिरिक्त उत्पादन को घरेलु व विदेशी किमतों में अंतर के कारण बाहर भेजने पर घाटा होगा।ऐसी स्थिति में देश में कृषि पदार्थों की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है जिस कारण पहले से ही संकटग्रस्त किसान और भी संकट में आ सकता है।

वास्तव में पूरे विश्व के किसानों के हालात किसी से छुपे नहीं है, पूरे विश्व के किसानों की संख्या हर वर्ष कम होती जा रही है। विकसित देश अपने किसानों को सीधा उनकें बैंक खातों में सहायता का पैसा देता है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में खेती करनें वाले केवल 25 लाख किसान है और वह उनकें खातें में प्रतिवर्ष लगभग 75 लाख रूपये देता है। जबकि भारत में बहुत छोटे किसान है कुल 14 करोड़ किसान परिवार है जिन्हें मात्र एक हजार रूपये ही आर्थिक सहायता मिलती हैं। ऐसे में भारत के लिए नैरोबी जैसे सम्मेलन और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाते है। पूरे विश्व के किसानों के लिए किसी ठोस निर्णय पर पहुंचने के लिए विकसित देशा को अपने दौहरे चरित्र से उभरता होगा केवल तभी उन्नत व समृद्ध कृषि का समना पूरा होगा। ❑❑

लेखक शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी, इन्द्री, करनाल, हरियाणा में एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) है।
email: ranbir_singh1974@yahoo.com

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

नौकरशाही के भरोसे विकास!

एनडीए सरकार का दूसरा वर्ष समाप्त होने को है। यूं तो सरकार की दिशा निर्धारित हो चुकी है। फिर भी नये वर्ष में दिशा का परिवर्तन की जरूरत दिखाई पड़ती है। एनडीए के पहले कार्यकाल का विवेचन करने के पहले वर्तमान चुनौती कुछ स्पष्ट हो जाती है। वाजपेयी सरकार ने कम से कम चार महान उपलब्धियाँ हासिल की थी। भारत को परमाणु शक्ति बनाया था, कारगिल युद्ध को जीता था, इनफारमेशन टेक्नालॉजी में भारत की पहल की नींव रखी थी, और गोल्डेन क्वाडरेंगल की महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप दिया था। फिर भी एनडीए 2004 में हार गई, चूँकि इन योजनाओं में आम आदमी के लिए कुछ नहीं था। सोनिया गांधी ने आम आदमी का मुद्दा उठाया और एनडीए को शिकस्त दी थी।

2009 में यूपीए ने पुनः चुनाव जीता। इस जीत का श्रेय किसानों की ऋण माफी तथा मनरेगा को जाता है। ये दोनों कदम स्पष्ट रूप से विकास के एजेंडे के विपरीत थे। ऋण माफी से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ा और हाइवे आदि के निवेश में कटौती हुई। मनरेगा से आम आदमी की दिहाड़ी में वृद्धि हुई। शहरी उद्यमियों तथा बड़े किसानों के लिए श्रमिक मंहगे हो गए। फिर भी यूपीए के शासनकाल में हमारी ग्रोथ रेट अच्छी रही। कारण कि ऋण माफी तथा मनरेगा ने आम आदमी के हाथ में क्रय शक्ति को बढ़ाया, बाजार में मांग बढ़ी ओर ग्रोथ हुई। जैसे परहेज करने से स्वास्थ में सुधार होता है उसी प्रकार अमीरों द्वारा ऊँचे प्रॉफिट से परहेज करने से अमीरों की ही आय में वृद्धि हुई थी।

पिछले वर्ष लोकसभा चुनावों में एनडीए ने पुनः ग्रोथ के सपने को परोसा था। अच्छे शासन, कालेधन की वापसी, रोजगार सृजन आदि के वायदों पर भरोसा करके जनता ने एनडीए को सत्ता पर बैठाया। लेकिन पिछले डेढ़ वर्षों में यह सपना चकनाचूर हो गया है। शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार में निश्चित रूप से कुछ कमी आई है। मंत्रियों की छवि अच्छी है। परंतु, जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार में कोई अंतर नही पड़ा है चूँकि सरकार को पीएमओ के

वाजपेयी सरकार ने चार महान उपलब्धियाँ हासिल की थी। भारत को परमाणु शक्ति बनाया, कारगिल युद्ध को जीता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत की पहल की नींव रखी, और गोल्डेन क्वाडरेंगल की महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप दिया था।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

आइएएस अधिकारी चला रहे है जिनके डीएनए में नौकरशाही के हितों को बढ़ाना है। कालेधन की वापसी तो दूर, धन के बाहर जाने की गति में तेजी आई है। प्रधानमंत्री ने स्वयं आश्चर्य जताया है कि भारतीय उद्यमी देश में निवेश करने के स्थान पर विदेशों में निवेश कर रहे है। यानी देश की पूँजी बाहर जा रही है। मध्यम वर्ग के रोजगार सृजन में कुछ गति अवश्य आई है परन्तु आम आदमी की दिहाड़ी अपनी जगह टिकी हुई है। बल्कि मंहगाई की मार से आम आदमी की क्रय शक्ति में ह्रास हुआ है।

प्रधानमंत्री ने स्वयं आश्चर्य जताया है कि भारतीय उद्यमी देश में निवेश करने के स्थान पर विदेशों में निवेश कर रहे है।

एनडीए द्वारा जिन कदमों को जनहितकारी बताया जा रहा है वे भी वास्तव में जनविरोधी है। जन–धन योजना के माध्यम से आम आदमी की बचत को बड़े उद्यमियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरे घर में काम करने वाली सहायिका के पास अनएथराइज्ड कॉलोनी में 80 गज का प्लाट था जिसे वह गिरवी रखकर लोन लेना चाहती थी। सरकारी बैंक ने साफ इंकार कर दिया। इससे जाहिर होता है कि जनधन योजना के अंतर्गत आम आदमी को लोन कम ही मिलेंगे। गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स के माध्यम से छोटे उद्योगों को वर्तमान में मिलने वाली टैक्स में छूट को समाप्त करने की योजना है। कहावत है पूत के पैर पालने मे दिखाई देते है। पिछले डेढ़ साल मे एनडीए की मूल जन विरोधी दिशा स्पष्ट दिखने लगी है।

2014 में सत्तारूढ़ होने के बाद दिल्ली में आप पार्टी ने एनडीए को अप्रत्याशित हार के गढ़े में डाल दिया। बिहार में नितीश, लालू गठबंधन ने एनडीए को आइना दिखाया था। एनडीए के नेतृत्व द्वारा बिहार की हार को नितिश–लालू के अनैतिक गठबंधन पर डाला जा रहा है। परंतु इस गठबंधन की सफलता के पीछे एनडीए के आम आदमी विरोधी चरित्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि एनडीए द्वारा वास्तव में जनहितकारी नीतियों को लागू किया जा रहा होता तो दिल्ली और बिहार का आम आदमी एनडीए के विरोध में वोट नहीं डालता। उपरी सतह पर आप तथा महागठबंधन की जीत भ्रष्टाचार और जाति समीकरण के कारण है परंतु इन जीत का असल कारण एनडीए की जनविरोधी नीतियां हैं। एनडीए ने न 2004 की हार से सबक लिया था न ही दिल्ली तथा बिहार की हार से सबक लेता दिख रही है।

चुनाव के बाद शेयर मार्किट को संभालने के लिए एनडीए सरकार ने तमाम नए क्षेत्रों में विदेशी निवेश की छूट को मंजूरी दे दी। यूपीए द्वारा स्वदेशी तथा विदेशी बड़ी कंपनियों के इंजन के पीछे भारत की ट्रेन को चलाने का मंत्र लागू किया गया था। इन बड़ी कंपनियों के द्वारा आम आदमी के रोजगार का तेजी से भक्षण किया जा रहा है जैसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी में लगे एक आटोमेटिक लूम से सैकड़ों छोटे पावरलूम का धंधा चौपट हो जाता है। एनडीए ने यूपीए के इस धूर्त महामंत्र को और मुस्तैदी से लागू किया है। जिस भोजन के कारण रोग उत्पन्न हुआ था उसी भोजन को अब बड़ी मात्रा में परोसा जा रहा है। मेरे एक मित्र के नवजात शिशु को ठंड लग गई। डाक्टरों ने एंटीबायोटिक दवा दी। बच्चे के स्वास्थ में सुधार नही हुआ तो डाक्टरों ने और स्ट्रांग एंटीबायोटिक दवा दी। बच्चे की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार एनडीए सरकार विदेशी निवेश से उत्पन्न हुए रोग का उपचार विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर कर रही है। सरकार की पॉलिसी बड़े उद्योगों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्धारित की जा रही हैं। इन लोगों की गाड़ी को प्रधानमंत्री पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से चला रहे है। मुसाफिर को जाना मुंबई है। प्रधानमंत्री उसे ईमानदारी से कोलकाता ले जा रहे है। जनता को चाहिए रोजगार। प्रधानमंत्री उसके रोजगार का भक्षण ईमानदारी से कर रहे है। मध्यम वर्ग को लाभ अवश्य हो रहा है परन्तु आम आदमी को इससे कोई लेना देना नही हैं।

एनडीए की सोच है कि उपरी वर्ग के विकास से कुछ आय ट्रिकल करके गरीब तक भी पहुंचेगी। इस सोच में आंशिक सच है। जैसे मिडिल क्लास द्वारा प्रापर्टी की खरीद करने से गरीब को कंस्ट्रक्शन वर्कर का रोजगार मिलता है। परंतु अपने देश में गरीब श्रमिकों की संख्या इतनी अधिक है कि इस ट्रिकल डाउन से आम आदमी को राहत कम ही मिलेगी। 2016 में एनडीए के सामने चुनौती है कि पिछले डेढ़ साल की जन विरोधी नीतियों में बदलाव करके वास्तव में आम आदमी को राहत देने की पालिसी लागू करे। ❑❑

स्वदेशी तकनीक का विकास करें

भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि– ''इंजीनियरिंग और शोध में वैज्ञानिक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, ऊर्जा, संवेदना और निष्पक्षता को केन्द्र में रखें। सरकार उनके लिये वैज्ञानिक शोध का रास्ता आसान बनायेगी। परंपरागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच अंतर पाटने की भी जरूरत है।'' इस बार इसका आयोजन मैसूर विश्वविद्यालय में किया गया। इस अधिवेशन का मुख्य विषय 'भारत में स्वदेशी विकास के लिए विज्ञान और तकनीक' है। इसके अलावा पर्यावरण और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और विकास, जलवायु परिवर्तन और समाज, आपदा प्रबंधन, शहरी विकास, जैव विविधता का संरक्षण, योग और न्यूरो साइंस आदि पर भी चर्चा की गयी। इसमें लगभग चार हजार प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

हर साल जनवरी के पहले हफ्ते में भारतीय विज्ञान कांग्रेस अपना वार्षिकोत्सव मनाती है। कोई भी सदस्य दस पंक्तियों का सारांश लिखकर इसमें भाग ले सकता है। कुछ विदेशी प्रतिनिधि भी बुला लिये जाते हैं। प्रचार के लिए प्रधानमंत्री से इसका उदघाटन करा लिया जाता है। वास्तव में इस प्रकार की संस्था से भारतीय विज्ञान को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। होना तो यह चाहिए था कि इसमें देश भर के वैज्ञानिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक मिलते और देश की समस्याओं पर चर्चा करके अपने–अपने क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की भावी रूपरेखा प्रस्तुत करते। सरकार भी उन्हें यह बताती कि देश में किन–किन क्षेत्रों में कैसी समस्याएं हैं और उनके समाधान के लिए किस तरह के शोध और विकास की जरूरत है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है लेकिन सारा का सारा वैज्ञानिक साहित्य पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों के कार्यों से भरा पड़ा है। विज्ञान और तकनीक के योगदान के मामले में भारत दुनिया में इक्कीसवें नम्बर पर है। इस रैंकिंग का आधार यह है कि कौन सा देश वैज्ञानिक शोध में कितनी हिस्सेदारी कर रहा है। यह हिस्सेदारी अनुसंधान पत्रों से तय होती है। विज्ञान और तकनीक में किसी देश के योगदान को वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों में पीएचडी करने वालों की संख्या से भी नापा जा सकता है। इस मामले में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है।

वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है लेकिन सारा का सारा वैज्ञानिक साहित्य पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों के कार्यों से भरा पड़ा है। विज्ञान और तकनीक के योगदान के मामले में भारत दुनिया में इक्कीसवें नम्बर पर है।
– निरंकार सिंह

हमारे पास सीएसआईआर जैसी संस्थाएं हैं, कई स्तरीय अनुसंधान केन्द्र है और विश्वविद्यालयों में विज्ञान के विभाग भी हैं। लेकिन सी.एस.आई.आर. का एक सर्वे बताता है कि हर साल जो करीब तीन हजार अनुसंधान पत्र तैयार होते हैं, उनमे कोई नया आइडिया नहीं होता। वैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिक संस्थानों की कार्यकुशलता का पैमाना वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन तथा पेटेंटों की संख्या है, लेकिन इन दोनों ही क्षेत्रों में गिरावट आई है। भारत में सील किए गये पेटेंटों की संख्या 1999–2000 में 1890 से गिर कर 2009–2010 में 1881 रह गयी है, जबकि रिसर्च एवं डेवलपमेंट (आर.एंड.डी.) पर खर्च बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 वर्ष में यह 232 प्रतिशत बढ़ गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2010 में भारत में कृषि, जीव,

विज्ञान, मेडिकल साइंस, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरी तथा भू–विज्ञान में शोध पत्रों में भारत का योगदान केवल 2.2 प्रतिशत रहा।

देश के कई वैज्ञानिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं पर ऐसे मठाधीशों का कब्जा है जिनका अकादमिक कार्य इस स्तर का नहीं है कि वे किसी संस्थान के निदेशक बनाये जाए लेकिन अपनी पहुंच के बल पर वे वैज्ञानिक अनुसंधान के मुखिया बने हुए हैं। विज्ञान की दुनिया में जोड़ घटाकर यों ही कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। विज्ञान में कुछ करने का मतलब है कि कोई नयी खोज या आविष्कार किया जाए। लेकिन जब चुके हुए लोग राजनीतिक तिकड़म और भाई–भतीजावाद से वैज्ञानिक संस्थानों, प्रयोगशालाओं एवं केन्द्रों के मुखिया होंगे तो क्या होगा? शायद इन्हीं सब कारणों से वैज्ञानिक समुदाय में कुण्ठा बढ़ रही है, जो त्यागपत्रों और आत्महत्या के रूप में भी समय–समय पर सामने आ चुकी है। यह कोई अकारण नहीं है, जिन भारतीय वैज्ञानिकों ने नाम कमाया है, वे विदेशों में बस चुके हैं। लगभग दस लाख भारतीय वैज्ञानिक डाक्टर और इंजीनियर आज देश से बाहर काम कर रहे हैं। आज भी प्रतिभा पलायन से अरबों डालर का नुकसान हो रहा है। चरक और सुश्रुत के बाद चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में हमारा योगदान शून्य रहा है। इसी तरह से भास्कराचार्य, आर्यभट के बाद गणित ज्योतिष में भी भारत ने कोई मौलिक अनुसंधान या खोज नहीं की है।

देश की 1138 औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाइयों में लगभग 60 हजार वैज्ञानिक कार्यरत हैं। लेकिन तकनीक के विकास में उनका योगदान नगण्य है। औद्योगिक जरूरतों और प्रयोगशालाओं के अनुसंधान के बीच कोई तालमेल नहीं है। वास्तव में विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए हमारे पास धन और साधनों की उतनी कमी नहीं जितना ही कहा जाता है। विदेशी सहायता का भी हम समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। अनुसंधान और तकनीक के विकास के लिए विदेशी सहायता की नमूना–जांच के लिए भारत के नियंत्रण लेखापरीक्षक ने 10 परियोजनाएं चुनी थीं। इनमें से पांच परियोजनायें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से और पांच परियोजनायें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से सम्बद्ध है। इन परियोजनाओं का कुल परिव्यय 824.04 करोड़ रूपये था। इनमें अनुदान का उपयोग 0.81 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत के हुआ। दो परियोजनाओं में उपयोग 50 प्रतिशत से भी कम रहा और दो अन्य परियोजनाओं में सहायता राशि के आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे। इन परियोजनाओं के प्रारम्भिक लक्ष्य की पूर्ति की समयावधि के बारे में 5 से 60 माह तक संशोधन किया गया लेकिन बावजूद चार मामलों में लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये। एक मामले में पूरी तरह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया, दो मामलों में लक्ष्य बिलकुल नहीं प्राप्त हुए थे। और 3 मामलों में मंत्रालय में सूचना भी उपलब्ध नहीं थी। स्पष्ट है कि कई परियोजनाओं के लक्ष्य धन होने के बावजूद भी पूरा नहीं किये जा सके।

विश्व बाजार के इस युग में अब उत्पादन के रहस्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तु बन गये हैं। ज्ञान और तकनीक को जब धन अर्जित करने के स्रोत के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन इस नये विश्व में स्वामित्वपूर्ण ज्ञान से ही संपदा अर्जित की जा सकती है। ज्ञान आधारित प्रतिस्पर्धा के युग में बौद्धिक सम्पदा अधिकारी नीतिगत उपकरण के रूप में उभरे हैं किसी भी देश को आत्मनिर्भरता में विज्ञान और तकनीक की शक्ति निर्विवाद रूप में सिद्ध हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रतिभावान और क्षमतावान वैज्ञानिक नहीं है जहां कहीं भी हमें चुनौती मिली है और लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, वहां हमने सफलता भी प्राप्त की है। राकेट, उपग्रह, मिसाइल और परमाणु विस्फोट के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों की शानदार सफलताएं इसी बात का प्रमाण है। दुनिया के अन्य देशों के आर्थिक विकास का सबसे अधिक सशक्त माध्यम तकनीक बन चुकी है। औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी देशों ने जो विकास किया है उसमें से लगभग एक तिहाई से आधा हिस्सा टैक्नालॉजी की प्रक्रिया से आया है। आर्थिक विकास के लिए टैक्नालॉजी के लगातार सुधार के साथ–साथ नये आविष्कार करना भी बहुत जरूरी है जब इस तरह के आविष्कार होते हैं तो इनसे पूरी औद्योगिक व्यवस्था बदल जाती है। हाल ही में हमने कम्प्यूटर और संचार तकनीक के क्षेत्र में हुयी उन्नति को देखा है।

भारत को यदि विश्व बाजार में अलग–थलग नहीं रहना है तो स्पष्ट रूप से हमें देश में विज्ञान और तकनीक के विकास का माहौल बनाना होगा। देश की जरूरत के हिसाब से विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान की प्राथमिकताएं तय की जानी चाहिए। विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान को अफसरशाही के शिकंजे से मुक्त कराकर देश के निर्माण के लिए समयबद्ध स्पष्ट कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। वास्तव में भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान ही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अर्थ–व्यवस्था को नया रूप देने और स्थानीय उद्योग को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ताकि वे सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। इसके लिए सभी पक्षों की मानसिकता में बदलाव लाना होगा। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को भी अपनी क्षमता और दक्षता के साथ योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन पर निचले स्तर तक नजर रखनी होगी। ❑❑

कब तक सहेंगे पीठ पर वार!

पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर हमले की योजना का खुलासा तो जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा, किंतु एक बात साफ है कि इस हमले के पीछे वही ताकतें हैं, जो भारत–पाक की दोस्ती की राह में रोड़ा डालती आई हैं।

– धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया

पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर आतंकी हमले के बार पूरे देश के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर यह कब तक हम दोस्ती का हाथ बढाएंगें? और बदले में पीठ पर वार कब तक खाएंगे? साम, दाम, दंड भेद की नीति पर चलकर पाकिस्तान को सबक सिखाना ही चाहिए। इस हमले के पीछे आतंकवादी संगठन जैश–ए–मोहम्मद का हाथ माना जा रहा है। जैश का सरगना कंधार हाईजैक के बदले रिहा किया गया मसूद अजहर है। रिहा होने के बाद इसने जैश को खडा किया। 2001 में संसद पर हमले में भी जैश का ही हाथ था। हालांकि जैश पर पाकिस्तान में प्रतिबंध है, लेकिन अल रहमत ट्रस्ट की आड़ में यह अपने काम को अंजाम देता है। पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर हमले की योजना का खुलासा तो जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा, किंतु एक बात साफ है कि इस हमले के पीछे वही ताकतें हैं, जो भारत–पाक की दोस्ती की राह में रोड़ा डालती आईं हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 25 दिसंबर को पाकिस्तान 'सरप्राइज विजिट' के बाद उम्मीद जगी थी कि नए साल में न सिर्फ रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी बल्कि भारत–पाक के रिश्तों में गर्माहट भी आएगी। मोदी की यात्रा के बाद भारत–पाक के बीच दोस्ती का रोडमेप तैयार करने के लिए दोनों देशों के विदश सचिव का 14–15 जनवरी को इस्लामाबाद में मिलना तय हुआ था। अब यह बैठक होगी या नहीं, इसे लेकर संशय बरकरार है। सवाल उठ रहा है कि गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच दोनों देश बातचीत के लिए कदम कैसे बढ़ा सकते हैं।

इसलिए चुना पठानकोट

पाक पोषित आतंकवादियों ने इस बार भी हमले के लिए पंजाब को चुना। आतंकवादियों ने पंजाब इसलिए चुना, क्योंकि एक तो यह बॉर्डर से महज 25 किमी की दूरी पर है। यहां एयरफोर्स के 18 विंग है। मिग–29, मिग–21 और अटैक चॉपर यहीं तैनात हैं। यहां से चीन तक निगरानी होती है। यहां हमले से पूरी दुनिया को संदेश गया है। दूसरा यह कि पंजाब

में जल्द ही चुनाव होने वाले है, इसलिए वहां अशांति भड़काना पाक के लिए फायदेमंद हो सकता है। तीसरा कारण यह कि कश्मीर भी अब पाकिस्तान की प्राथमिकता में नहीं हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली की विशेष कश्मीर कमेटी है, लेकिन पिछले दो साल से इस विशेष कश्मीर कमेटी की एक भी बैठक नही हुई है। इस विशेष कमेटी के अध्यक्ष को केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। विशेष कमेटी का गठन कश्मीर के लोगों पर भारतीय सुरक्षा बलों की कथित ज्यादतियों को विभिन्न फोरम पर उठाने और कश्मीर में जनमत संग्रह के लिए अंर्तराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए किया गया। कश्मीरियों के प्रति पूरे पाकिस्तान के समर्थन का इजहार करने के लिए इसमें सभी प्रांतों और दलों के चुने हुए प्रतिनिधियों को जगह दी जाती है। कमेटी के लोग पाक अधिाकृत कश्मीर जाकर लोगों को यह अहसास दिलाते हैं कि पूरा देश उनके साथ है, लेकिन पिछले कई वर्षो से न तो कमेटी की बैठक हुई हैं और न ही कमेटी ने पीओके का दौरा किया है।

सुरक्षा एजेंसियों से चूक

पाकिस्तान में सत्ता के दो केंद्र हैं। एक तरफ चुनी हुई सरकार है, तो दूसरी तरफ कट्टरपंथी संगठन और निरंकुश सेना। सेना और कट्टरपंथी

संगठन सरकार पर भी हावी हैं, इसलिए पाकिस्तान में अराजकता और आतंकवाद का नंगा नाच चल रहा है। सच तो यही है कि जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व है, तब तक भारत में आतंकवाद नासूर बनकर फूटता ही रहेगा।

इस्लामाबाद और दिल्ली के रिश्ते एकदम तो नहीं सुधरने वाले। यह रिश्ते इतने पेचीदा हो गए हैं कि एकाएक तो नहीं सुलझने वाले। नरेन्द्र मोदी की सरप्राइज विजिट और बर्थडे डिप्लोमेसी अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन सिर्फ बात से बात नहीं बनने वाली। दोनों देशों के बीच राजनयिक संवाद जारी रहना चाहिए, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ठोस एवं प्रभावी रणनीति भी बनना चाहिए। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमले के बाद यह साफ है कि कहीं सुरक्षा एजेंसियों से चूक तो हुई है। हमारे

जवान बहादुरी से लड़े और आतंकवादियों के मंसूबो को पूरी तरह कामयाब नहीं होने दिया लेकिन अगर सुरक्षा एजेंसियां चौकस होती तो आतंकवादी भारत की जमीन पर पैर नहीं रख पाते।

धोखा दे रहा पाक

पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहील शरीफ कह रहे है कि 2016 में पाकिस्तान से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार और अपराध के बीच गठबंधन है और इस गठबंधन को तोड़ने के लिए पूरे देश को सशस्त्र बलों को समर्थन देने की आवश्यकता है, लेकिन सेना प्रमुख का यह बयान सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाला लगता है। पाकिस्तानी सेना और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू है। 2008 में मुंबई हमला से लेकर 2015 के गुरदासपुर तक अनेक नजीरें हमारे पास हैं। गुरदासपुर के बाद पठानकोट हमले से तय है कि सेना की देखरेख में कितनी बारीकी से योजना बनाई गई थी। इसे आम आतंकवादी हमला नहीं कहा जा सकता। संसद पर हमला हो या फिर भारतीय सेना के ठिकानों पर, यह सीधे–सीधे भारत पर हमला है। अब रक्षात्मक उपाय की बजाय आतंकवाद को उसी की मांद मे चुनौती देने का वक्त भी आ गया है। ❑❑

dharmendrasinghbhadauria@yahoo.co.in

पेरिस जलवायु समझौता

यह इश्क नहीं आसां

विकसित की तुलना में गरीब व विकासशील देश कम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं; जबकि कार्बन उत्सर्जन कटौती की कवायद में उनका विकास ज्यादा प्रभावित होगा; लिहाजा, विकसित देश घाटा भरपाई की जिम्मेदारी लें।
– अरूण तिवारी

किसी और नजरिए से हम पेरिस जलवायु समझौते के नफा–नुकसान की तलाश तो कर सकते हैं, किंतु यह नहीं कह सकते कि यह समझौता पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि करेगा; अर्थात यह समझौता, तापमान वृद्धि रोकने में तो कुछ न कुछ मदद ही करने वाला है। पेरिस जलवायु समझौते की यही उपलब्धि है। ''पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।'' – तारीख 12 दिसंबर, 2015, समय–शाम 7.16 मिनट पर हुई फ्रांसीसी विदेश मंत्री लारेंट फेबियस द्वारा की गई यह उद्घोषणा, तत्पश्चात् तालियों की गडगडाहट, चियर्स के शब्द बोल, सीटियों की गूंज और इन सबके बीच कई चेहरों को तरल कर गई, हर्ष मिश्रित अश्रु बूंदों का संदेश भी यही है। इसका संदेश यह भी है कि किसी न किसी को इस समझौते का लंबे समय से इंतजार था। इस समझौते को इस मुकाम तक लाने के लिए एक लंबी और मुश्किल कवायद की गई थी।इसी कवायद के चलते यूरोपीय संघ के राष्ट्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में स्वैच्छिक कटौती की कानूनी बाध्यता को स्वीकारा, अमेरिका ने 'घाटा और क्षति' की शब्दावली को और भारत–चीन ने वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न जाने देने की आकांक्षा को। 134 देश, आज विकासशील की श्रेणी में हैं। उनके हक में माना गया कि विकसित की तुलना में गरीब व विकासशील देश कम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं; जबकि कार्बन उत्सर्जन कटौती की कवायद में उनका विकास ज्यादा प्रभावित होगा; लिहाजा, विकसित देश घाटा भरपाई की जिम्मेदारी लें। इसके लिए 'ग्रीन क्लाइमेट फंड' बनाना तय हुआ। तय हुआ कि वर्ष 2025 तक इस विशेष कोष में 100 अरब डॉलर की रकम जमा कर दी जाये।

यूं बंधे भारत–चीन

वर्ष 1992 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा की जा रही वैश्विक जलवायु समझौते की कोशिशों की नाकामयाबी को भी देखें, तो कह सकते हैं कि यह सब सचमुच आसान नहीं था। इसे

मुमकिन बनाने के लिए यह सम्मेलन भारत जैसे देशों को दबाव में लाने की कोशिशों से भी गुजरा। भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के बिना इस समझौते को अधूरा मानने की बात कही गई। इसके लिए दुनिया भर में बाकायदा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। तैयारी बैठकों में चले खेल से दुखी प्रतिनिधि कहते हैं कि सम्मेलन एक नाटक था; असल में अम्ब्रेला समूह के साथ मिलकर सम्मेलन और समझौते की पटकथा पहले से लिख दी गई थी। अमेरिका ने गंदी राजनीति खेली। उसके संरक्षण में 100 देशों का एक गुट अचानक सामने आया और उसने उसके मुताबिक समझौता कराने में कूटनीतिक भूमिका निभाई। कहने वाले ये भी कहते हैं कि अमेरिका ने भारत के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना। एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने अपने एक साक्षात्कार में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत को ही एक चुनौती करार दे दिया, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति, भारत के नेतृत्वकारी भूमिका की सराहना करते रहे। जो खुद नहीं कह सके,उसे मीडिया से कहला दिया। मशहूर पत्रिका टाइम ने भारत की भूमिका की तारीफ की, तो न्यूयार्क टाइम्स ने भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कार्बन बजट में भारत की अच्छी–खासी हिस्सेदारी संबंधी बयान को लेकर लानत–मलानत की। इसे दबाव कहें या फिर रायनय कौशल, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री से बैठक, फोन वार्ताओं और फ्रांस के रायनय कौशल का असर यह रहा कि जो भारत और चीन, कार्बन उत्सर्जन कम करने की कानूनी बाध्यता के बंधन में बंधने से लगातार इंकार करते रहे थे, संयुक्त राष्ट्र का पेरिस सम्मेलन, दुनिया की सबसे बडी आबादी और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन दो मुल्कों को बांधने में सफल रहा। 1997 में हुई क्योटो संधि की आयु 2012 में समाप्त हो गई थी। तभी से जिस नई संधि की कवायद शुरु हुई थी, वह कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 'कॉप21' के साथ संपन्न हुई।

पेरिस जलवायु समझौते को कानून में बदलता देखने के लिए हम सभी को अभी अगले पृथ्वी दिवस का इंतजार करना है।

क्या कहते हैं समीक्षक ?

गौर कीजिए कि पेरिस जलवायु समझौता, अभी सिर्फ एक समझौता भर है। कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में से 55 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देशों में से 55 देशों की सहमति के बाद समझौता एक कानून में बदल जायेगा। यह कानून, सहमति तिथि के 30 वें दिन से लागू हो जायेगा। इसी के मद्देनजर तय हुआ है कि सदस्य देश 22 अप्रैल, 2016 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचकर समझौते पर विधिवत् हस्ताक्षर करेंगे। जाहिर है कि पेरिस जलवायु समझौते को कानून में बदलता देखने के लिए हम सभी को अभी अगले पृथ्वी दिवस का इंतजार करना है। किंतु 'कॉप21' के समीक्षक इसका इंतजार क्यों करें ? कॉप21 के नतीजे में जीत–हार देखने का दौर तो सम्मेलन खत्म होने के तुरंत बाद ही शुरु हो गया था। किसी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि कहा, तो किसी ने इसे धोखा, झूठ और कमजोर करार दिया; खासकर, गरीब और विकासशील देशों के हिमायती विशेषज्ञों द्वारा समझौते को आर्थिक और तकनीकी तौर पर कमजोर बताया जा रहा है। विशेषज्ञ प्रतिक्रिया है कि जो सर्वश्रेष्ठ संभव था, उससे तुलना करेंगे, तो निराशा होगी। जलवायु मसले पर वैश्विक समझौते के लिए अब तक हुई कोशिशों से तुलना करेंगे, तो पेरिस सम्मेलन की तारीफ किए बिना नहीं रहा जा सकता। भारत के वन एवम् पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावेडकर ने भी माना कि यह समझौता, हमें तापमान को दो डिग्री से कम रखने के मार्ग पर नहीं रखता।

विरोध के बिंदु

विज्ञान पर्यावरण केन्द्र की महानिदेशक सुनीता नारायण का स्पष्ट मत है कि वायुमंडल में विषैली गैसों का जो जखीरा तैर रहा है, वह पैसे के ऊंचे पायदान पर बैठे देशों की देन है। उन्होने अपना कार्बन उत्सर्जन घटाने का न पूर्व में कोई विशेष प्रयास किया है और न अब करने के इच्छुक हैं। स्वच्छ ऊर्जा के लिए उन्होने पूर्व में न उन्होने धन देकर कोई मदद की, न तकनीक। फिर भी वे उम्मीद करते हैं कि विकासशील देश, विकसित देशों की निगरानी में स्वच्छ ऊर्जा में कटौती के लिए बाध्य किए जायें।

समझौते को नाकाफी अथवा सौदेबाजी बताने वालों का मुख्य तर्क यह है कि जो जिम्मेदारियां, विकसित देशों के लिए बाध्यकारी होनी चाहिए थी, वे बाध्यकारी खण्ड में नहीं रखी गई। कायदे से विकसित देशों को चाहिए कि वे वायुमंडल के कार्बन खण्ड में उतना स्थान खाली करें, जितना उन्होने दूसरे देशों के हिस्से का घेर रखा है। किंतु समझौते के बाद अब विकसित देशों के लिए कार्बन उत्सर्जन कटौती

लक्ष्य की कोई वैधानिक बाध्यता नहीं रह गई है। कहना न होगा कि विकसित देश, बडी चाालाकी के साथ भाग निकले। वे, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों की क्षतिपूर्ति की अपनी जवाबदेही को विकासशील देशों के कंधे पर स्थानान्तरित करने में सफल रहे। सर्वाधिक विरोध इस बात का है कि 'ग्रीन क्लाइमेट फंड' के लिए 100 अरब डॉलर धनराशि एकत्र करना तो बाध्यकारी बनाया गया है, किंतु कौन सा देश कब और कितनी धनराशि देगा; यह बाध्यता नहीं है। समझौते में कहा गया है कि 2025 तक अलग–अलग देश अपनी सुविधा से 100 बिलियन डॉलर के कोष में योगदान देते रहें।

गौर कीजिए कि समझौते के दो हिस्से हैंः निर्णय खण्ड और समझौता खण्ड। निर्णय खण्ड में लिखी बातें कानूनन बाध्यकारी नहीं होंगी। समझौता खण्ड की बातें सभी को माननी होंगी। विकासशील और गरीब देशों को इसमें छूट अवश्य दी गई है, किंतु संबंधित न्यूनतम अंतराष्ट्रीय मानकों की पूर्ति करना तो उनके लिए भी बाध्यकारी होगा। मलाल इस बात का भी है कि 100 अरब डॉलर के कार्बन बजट को एक हकदारी की बजाय, मदद की तरह पेश किया है; जबकि सच यह है कि कम समय में कार्बन उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य का पाने लिए जिन हरित तकनीकों को आगे बढ़ाना होगा, वे मंहगी होंगी। गरीब और विकासशील देशों के लिए यह एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ की तरह होगा। निगरानी व मूल्यांकन करने वाली अतंर्राष्ट्रीय समिति उन्हे ऐसा करने पर बाध्य करेंगी। न मानने पर कार्बन बजट में उस देश की हिस्सेदारी रोक देंगे। बाध्यता की स्थिति में तकनीकों की खरीद मजबूरी होगी। इसीलिए सम्मेलन पूर्व ही मांग की गई थी कि उत्सर्जन घटाने में मददगार तकनीकों को पेटेंटमुक्त रखना तथा हरित तकनीकी का हस्तांतरण को मुनाफा मुक्त रखना बाध्यकारी हो, किंतु यह नहीं हुआ। विकसित व अग्रणी तकनीकी देश, इन मसलों पर स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करने में आनाकानी बरतते रहे। वे चालाकी में हैं कि इस पर पेरिस सम्मेलन के बाहर हर देश से अलग–अलग समझौते की स्थिति में अपनी शर्तों को सामने रखकर दूसरे हित भी साध लेंगे। मसौदा, निश्चित तौर पर तकनीकी हस्तांतरण के मसले पर कमजोर है। नये मसौदे में हवाई यात्रा के अंतर्राष्ट्रीय यातायात तंत्र पर बात नहीं है। सच्चाई यह है कि कार्बन बजट के साथ–साथ अन्य बाध्यतायें न होने से अमेरिका और हरित तकनीकों के विक्रेता देश खुश हैं। राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने राहत की सांस ली है। वे जानते हैं कि बाध्यकारी होने पर सीनेट में उसका घोर विरोध होता। सम्मेलन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को बार–बार बधाई के पीछे एक बात संभवतः यह राहत की सांस भी है।

सच यह है कि कम समय में कार्बन उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य का पाने लिए जिन हरित तकनीकों को आगे बढ़ाना होगा, वे मंहगी होंगी। गरीब और विकासशील देशों के लिए यह एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ की तरह होगा।

भारतीय पक्ष

उक्त परिदृश्य के आइने में कह सकते हैं कि पेरिस सम्मेलन, आशंकाओं के साथ शुरु हुआ था और आशकांओं के साथ ही खत्म हुआ, किंतु इसमें भारत ने अहम भूमिका निभाई; इसे लेकर किसी को कोई आशंका नहीं है; न विशेषज्ञ स्वयंसेवी जगत को और न मीडिया जगत को। इस सम्मेलन में भारत, विकासशील और विकसित देश की अंतर्रेखा खींचने में समर्थ रहा। वह समझौते में 'जलवायु न्याय', 'टिकाऊ जीवन शैली' और 'उपभोग' जैसे शब्दों के शामिल कराने में सफल रहा। हम गर्व कर सकते हैं कि सौर ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय मिशन को लेकर फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने वाकई नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। भारत ने कार्बन उत्सर्जन में स्वैच्छिक कटौती की महत्वाकांक्षी घोषणा की; तद्नुसार भारत, वर्ष 2005 के अपने कार्बन उत्सर्जन की तुलना में 2030 तक 30 से 35 फीसदी तक कटौती करेगा। इसके लिए भारत, अपने बिजली उत्पादन के 40 प्रतिशत हिस्से को कोयला जैसे जीवश्म ऊर्जा स्त्रोतों के बिना उत्पादित करेगा। 2022 से एक लाख, 75 हजार मेगावॉट बिजली, सिर्फ अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से पैदा करेगा। एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर भारत ने 2030 तक 2.5 से तीन अरब टन कार्बन डाई ऑक्साइड अवशोषित करने का भी लक्ष्य रखा है। इसके लिए भारत वन क्षेत्र में पर्याप्त इजाफा करेगा। भारत, इस कार्य को अंजाम देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कोष का गठन करेगा। भारत ने यह घोषणा, युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाईमेट चेंज (यू एन एफ सी सी) के समक्ष की है। भारत ने इस घोषणा को इंटेडेंट नेशनली डिटरमांइड कन्ट्रीब्युशन (आई एन डी सी) का नाम दिया।

इन कवायदों के बदले में भारत को 'ग्रीन क्लाइमेट फंड' नामक विशेष कोष से मदद मिलेगी। यह पैसा बाढ़, सुखाङ, भूकम्प जैसी किसी प्राकृतिक आपदा की एवज में नहीं, बल्कि भारतीयों के रहन–सहन और रोजी–रोटी के तौर–तरीकों में बदलाव के लिए मिलेगा। अन्य पहलू यह होगा कि किंतु जीवाश्म

ऊर्जा स्त्रोत आधारित बिजली संयंत्रों को विदेशी कर्ज मिलना लगभग असंभव हो जायेगा। अन्य देशों की तरह भारत को भी हर पांच साल बाद बताना होगा कि उसने क्या किया। गौर करने की बात यह भी है एक वैश्विक निगरानी तंत्र बराबर निगाह रखेगा कि भारत कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। निगरानी, समीक्षा तथा मूल्यांकन – ये कार्य एक अंतर्राष्ट्रीय समिति की नजर से होगा। असल समीक्षा कार्य 2018 से ही शुरु हो जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर समीक्षा होगी।

भारतीय आशंका

अंतर्राष्ट्रीय मानक, भारत की भू–सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक विविधता के अनुकूल हैं या नहीं? समझौते के कारण भारत किन्ही नई और जटिल बंदिशों में फंस तो नहीं जायेगा? भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्ष 2008 में भी राष्ट्रीय कार्ययोजना पेश की थी। अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, कचरे का बेहतर निस्तारण, पानी का कुशलतम उपयोग, हिमालय संरक्षण, हरित भारत, टिकाऊ कृषि व पर्यावरण ज्ञान तंत्र का विकास–उसके आठ लक्ष्य क्षेत्र थे। गत् सात वर्षों में हम कितना कर पाये ? आगे नहीं कर पायेंगे, तो क्या हमें कार्बन बजट में अपना हिस्सा मिलेगा? नहीं मिला, तो भारत की आर्थिकी किस दिशा में जायेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्बन उत्सर्जन घटाने और अवशोषण बढ़ाने की हरित तकनीकों को लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समिति के इशारे पर नाचने पर मजबूर हो जायेंगे?

भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन औसत दुनिया के कई देशों की तुलना में काफी कम है, किंतु कुल उत्सर्जन में भारत, दुनिया का तीसरा बडा देश है। सकल घरेलु उत्पाद दर की दृष्टि से भी भारत, दुनिया का तीसरा अग्रणी देश है। इस रैंकिंग के

आधार पर आगे चलकर भारत को कहा जा सकता है कि वह ग्रीन क्लाइमेट फंड से लेने की बजाय, उसकी तुलना में कम उत्सर्जन करने वालों को दे। यूं भी भौतिक–आर्थिक विकास और शहरीकरण की जिस मंजिल की ओरभारत आगे बढ़ चला है, उस मंजिल की राह में औद्योगिक,घरेलु और कृषि ही नहीं, वाणिज्यिक क्षेत्र की ऊर्जा मांग में बडा इजाफा होने वाला है। अपने विकास का मॉडल बदले बगैर, भारत की ऊर्जा मांग का आंकडा घटने की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल, भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन का बडा स्त्रोत माने जाने वाले कोयले से ही हो रहा है। विकल्प हैं, किंतु विकल्पों के लिए जो तैयारी और वक्त चाहिए; क्या पेश लक्ष्य हमें इतना वक्त देता है कि हम कोयला खनन और ताप विद्युत को उतने समय में अलविदा कह सकें? पनबिजली संयंत्र, औद्योगिक संयंत्र, फसल जलाव, वाहन व कचरा आदि कार्बन उत्सर्जन के अन्य मुख्य स्त्रोत हैं। कचरे की तुलना में उसके वैज्ञानिक निष्पादन की हमारी क्षमता बेहद कम है। इन स्थितियों के मद्देनजर,क्या कार्बन कटौती के पेश लक्ष्य की पूर्ति हेतु तय समय सीमा, भारत के लिए एक मुश्किल चुनौती नहीं बनने वाली? निस्संदेह, हवा–पानी ठीक करने का भारतीय मोर्चा भी इन तमाम आशंकाओं से मुक्त नहीं है। गौर कीजिए कि कार्बन उत्सर्जन, अब किसी सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडा विषय है। क्या होगा ? कोई ताज्जुब नहीं कि वर्ष 2023 आते–आते भारत, कार्बन उत्सर्जन में कटौती की अपनी स्वैच्छिक उद्घोषणा का उल्लंघन करने पर स्वयं ही विवश हो जाये। जो कुछ होगा, वह भारत के संकल्प, विकास मॉडल, सावर्जनिक परिवहन प्रणाली की व्यापकता, सामर्थ्य और वैश्विक बाजारू शक्तियों की मंशा पर निर्भर करेगा।

भारत की आर्थिकी किस दिशा में जायेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्बन उत्सर्जन घटाने और अवशोषण बढ़ाने की हरित तकनीकों को लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समिति के इशारे पर नाचने पर मजबूर हो जायेंगे?

कितना वाजिब आशंका का आधार?

गौर कीजिए कि इन आशंकाओं का आधार आर्थिक है और जलवायु परिवर्तन के मसले पर विरोधी स्वरों का भी। क्या यह दुखद नहीं कि तापमान वृद्धि रोकने जैसे जीवन रक्षा कार्य में भी

प्रदूषण, जान लेता है। प्रश्न यह है कि आखिरकार कोई प्रदूषक, सिर्फ दण्ड भरकर किसी की हत्या के अपराध से कैसे मुक्त हो सकता है?

दुनिया, मसलों में बंट गई है। दुनिया, 'प्रदूषण करो, दण्ड भरो' के सिद्धांत की दुहाई दे रही है। आर्थिक–सामाजिक न्याय की दृष्टि से आप इसे सही मानने को स्वतंत्र हैं, किंतु यह सही है नहीं। क्या पैसे पाकर आप, ओजोन परत के नुकसानदेह खुले छेदों को बंद कर सकते हैं? धरती पर जीवन की नर्सरी कहे जाने वाली मूंगा भित्तियां पूरी तरह नष्ट हो जायेंगी, तब जीवन बचेगा; क्या दुनिया की बडी से बडी अर्थव्यवस्था इसकी गारंटी दे सकती है?

प्रदूषण, जान लेता है। प्रश्न यह है कि आखिरकार कोई प्रदूषक, सिर्फ दण्ड भरकर किसी की हत्या के अपराध से कैसे मुक्त हो सकता है? 'प्रदूषण करो और दण्ड भरो' के इसी सिद्धांत के कारण, आज भारत में भी प्रदूषक, प्रदूषण करने से नहीं डरते। यह सिद्धांत, प्रदूषण रोकने की बजाय, भ्रष्टाचार बढाने वाला सिद्ध हो रहा है। जब तक यह सिद्धांत रहेगा, पैसे वाले प्रदूषक मौज करेंगे और गरीब मरेंगे ही मरेंगे ही। इस सिद्धांत के आधार पर जलवायु परिवर्तन के कारकों पर लगाम लगाना कभी संभव नहीं होगा। जरूरत, इस सिद्धांत को चुनौती देकर, प्रदूषकों को मुश्कें कसने की है। जरूरी है कि एक सीमा से अधिक प्रदूषण को, हत्या के जानबूझकर किए प्रयास की श्रेणी में रखने के राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय कानून बनें। कानून की पालना की पुख्ता व्यवस्था बने। आगे चलकर, धीरे–धीरे प्रदूषण सीमा को घटाकर शून्य पर लाने की समय सीमा तय हो। शून्य प्रदूषण पर पहुंचे उत्पादनकर्ता के लिए प्रोत्साहन प्रावधान भी अभी सुनिश्चित हो। जो अंग जितना अधिकतम यत्न कर सकता है, उसे उतनी क्षमता और पूरी ईमानदारी से अधिकतम उतना साझा करना चाहिए। संकट में साझे का सामाजिक सिद्धांत यही है। इसी सिद्धांत को आगे रखकर ही हमें पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर आगे बढ़ना चाहिए।

यूं भी हम याद करें कियोजनायें और अर्थव्यवस्थायें, उपलब्ध अर्थ के आधार पर चल सकती हैं, पर 'अर्थ' यानी पृथ्वी और इसकी जलवायु नहीं। जलवायु परिवर्तन का वर्तमान संकट, अर्थ संतुलन साधने से ज्यादा, जीवन संतुलन साधने का विषय है। स्वयं को एक अर्थव्यवस्था मानकर, यह हो नहीं सकता। हमें पृथ्वी को शरीर और स्वयं को पृथ्वी का एक शारीरिक अंग मानना होगा। प्राण बचाने के लिए अंग एक–दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करते। प्राकृतिक संरक्षण का सिद्धांत है। भारत को भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि दुनिया के दूसरे देश क्या करते हैं? इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम उन्हे उनके दायित्व निर्वाह की पूर्ति हेतु विवश करने की मुहिम से पीछे हट जायें। उन पर नजर रखें; उचित करने को दबाव बनायें; किंतु हम यह तभी कर सकते हैं, जब पहले हमने खुद उचित कर लिया हो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के उत्सर्जन की स्वैच्छिक कटौती के भारत प्रस्ताव की घोषणा के लिए गांधी जयंती, 2015 के दिन को चुना। महात्मा गांधी ने दूसरों से वही अपेक्षा की, जो पहले खुद कर लिया। भारत के पास प्रतीक्षा करने का विकल्प इसलिए भी शेष नहीं है, चूंकि भारत की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियां अन्य देशों से बहुत भिन्न, विविध व जटिल हैं। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

जलवायु परिवर्तन से कृषि क्षेत्र का विकास प्रभावित

– गार्गी परसाई –

वर्ष 2015 कृषि क्षेत्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण साल था। देश के कई हिस्सों में रुखे मौसम और सूखे के कारण किसानों के लिए यह परेशानियों का लगातार दूसरा वर्ष था, जिसने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के तत्काल समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया। गेहूं की रबी बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 20.23 लाख हेक्टेयर कम हुई है, दालों और सब्जियों के दाम लगातार ऊंचे बने हुए हैं। दक्षिण–पश्चिमी मानसून इससे पिछले वर्ष में 12 प्रतिशत की कमी के बाद 2015 में लंबी अवधि औसत के सामान्य स्तर से 14 प्रतिशत कम रहा, जिसका असर खरीफ फसलों पर पड़ा। इसके बाद जो उत्तर–पूर्वी मानसून आया, वह तमिलनाडू एवं आस–पास के क्षेत्रों में भारी विनाश का कारण बना। इससे वहां अभूतपूर्व बाढ़ का संकट आया, जिसने पूरी तरह धान एवं नकदी फसलों को बर्बाद कर दिया।

दाल एवं तिलहनों का उत्पादन पिछले कई वर्षों से मांग की तुलना में लगातार कम होता रहा है। इस साल अनाजों के उत्पादन को लेकर बड़ी चिंताएं बनी हुई है हालांकि वर्तमान में देश में खाद्यान अधिशेष मात्रा में है पर विशेषज्ञ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कम से कम 62.5 मिलियन टन सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न मुहैया कराए जाने की कानूनी प्रतिबद्धता की ओर ध्यान दिलाते हैं। यही कारण है कि देश के किसान अच्छी फसल अर्जित करने के लिए बेहतर मौसम स्थितियों को लेकर अभी से चिंताग्रस्त है।

इस वर्ष कम नौ राज्यों ने सूखाग्रस्त जिलों की घोषणा की है। ये हैं कर्नाटक, छत्तीसगढ, मध्य्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एवं झारखंड। तमिलनाडू में अधिकांश जिलें तो इस वर्ष बाढ़ से बुरी तरह ग्रस्त रहे हैं। 2014–15 के दौरान भी हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के कई जिलें सूखे की चपेट में रहे थे।

2014–15 में खाद्यान्न उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान 252.68 मिलियन टन का था, जो 2013–14 से 265.04 मिलियन टन के उत्पादन से 12.36 मिलियन टन कम है। ऐसा गेहूं के उत्पादन में 6.19 मिलियन टन की गिरावट की वजह से है। चावल का उत्पादन भी थोड़ा कम रहा था। दालों का उत्पादन 2014–15 में 19.24 मिलियन टन से कम होकर 17.20 मिलियन टन रह गया, जिसकी वजह से इन खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व तेजी का संकट उत्पन्न हो गया। उदाहरण के लिए अरहर की कीमतें एक साल पहले के 75 रुपए प्रति किलोग्राम से उछल कर 199 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई और अभी भी ये कीमतें नियंत्रण के बाहर हैं। न केवल अरहर, उरद की कीमतें बल्कि खुदरा बाजार में लगभग सभी प्रमुख दालों की कीमतें वर्तमान में भी लगभग 140 रुपए प्रति किलोग्राम के आस–पास बनी हुई हैं।

सरकार ने प्रमुख दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 275 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की है। सरकार को इस वर्ष प्याज एवं दालों के लिए बार–बार बाजार में हस्तक्षेत्र करने को बाध्य होना पड़ा है। केवल नियमित सब्जियों एवं फलों की बात न करें, आलू और टमाटर तक की कीमतें इस वर्ष आसमान छूती रही है। मौसम के प्रारंभ में मटर की कीमतें 110 रुपए प्रति किलोग्राम के उच्च स्तर पर चली गई थी। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए की एक संचित राशि के साथ एक मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की है। इस वर्ष कुछ फंड ऐसे राज्यों में दालों की सब्सिडी प्राप्त बिक्री के लिए जारी किए गए थे, जिन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को किफायती दरों पर दाल मुहैया कराने के लिए अन्वेषक योजनाएं प्रस्तुत की थी।

यह देखते हुए कि 2015–16 के लिए उत्पादन अनुमान अभी भी 2013–14 की बंपर फसल की तुलना में कम है, सरकार ने अरहर एवं उरद दालों के लिए 1.5 लाख टन का बफर स्टॉक सृजित करने का फैसला किया है, जिसे बाजार दरों पर सीधे किसानों द्वारा प्राप्त किया जाएगा। सूखे की परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें महज 33 फीसदी की तुलना में अब 50 फीसदी तक नष्ट फसल क्षेत्र पर विचार करना तथा राहत राशि में 50 की बढ़ोत्तरी करना शामिल है। ❑❑

*गार्गी परसाई दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

बैंक से लोन लेना हुआ सस्ता

भारतीय स्टेट बैंक के बाद निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने बेस रेट या कर्ज की न्यूनतम दर को 0.05 फीसदी घटा कर 9.30 फीसदी कर दिया है। बेस रेट में कमी से सभी कर्ज की दरों में गिरावट आएगी। एचडीएफसी बैंक के खजांची आशीष पार्थसारथी ने कहा कि तिमाही समीक्षा के आधार पर बैंक ने बेस रेट घटाने का फैसला किया है।

BSNL ने की सस्ती कॉल

बीएसएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनुपम श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए हमने नए ग्राहकों के लिए पहले दो माह में मोबाइल दरों में 80 फीसदी तक कटौती कर दी है, जिससे उन्हें हमारी सेवाओं में सुधार का अनुभव मिल सके। कॉल दरें प्रति मिनट और प्रति सेकेंड बिलिंग प्लान के लिए घटाई गईं हैं और यह ग्राहक के बीएसएनएल ज्वाइन करने के पहले दो माह तक के लिए ही वैध होगी।

नोटों पर दिख सकते हैं अंबेडकर और विवेकानंद

जल्द ही आपके नोटों पर गांधीजी के अलावा भीमराव अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें भी देखने को मिल सकती हैं। ये प्रस्ताव नरेंद्र जाधव ने दिया है, जो अंबेडकर की 125वीं जयंती के लिए मोदी की अगुवाई में बनी नेशनल कमेटी के सदस्य है। इस कमेटी में कुल 6 सदस्य हैं। जाधव ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन की करंसी में भी कई शख्सियतों की तस्वीरें छपी रहती हैं। ऐसे में इस कदम को भारत में भी उठाया जा सकता है।

शुरू होगी जम्मू से हरिद्वार के लिए ट्रेन

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने विश्वास जताया कि रेलवे आने वाले वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2.5 फीसद वृद्धि लाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार विशेष रूप से अनुसंधान व विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है ताकि रेलवे देश की आर्थिक वृद्धि के इंजन के रूप में काम करे। प्रभु ने बताया कि रेलवे इस साल मार्च में जम्मू और हरिद्वार के बीच नई ट्रेन शुरू करेगा। उन्होंने कहा, 'जम्मू कश्मीर एक अहम राज्य है और वह हमारे हृदय के करीब है। घाटी को दिल्ली और देश के हृदय से जोड़ना हमारा दायित्व था'। उन्होंने कहा, 'हम रेलवे के माध्यम से जम्मू कश्मीर को और जोड़ने की योजना बना रहे हैं'।

उन्होंने कहा कि जम्मू और हरिद्वार को जोड़ने वाली एक ट्रेन इस साल शिवरात्रि से पहले शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी के लिए एक विशेष ट्रेन भी शीघ्र शुरू की जाएगी। मोदी सरकार बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए रेलवे के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है ताकि लोग रेल यात्रा का आनंद ले सकें।

सस्ता होगा Setup Box, कम पैसों में देख सकेंगे TV

घरेलू विनिर्माताओं को सशर्त पहुंच प्रणाली (कैस) के लिए देश में ही विकसित समाधान उपलब्ध कराए जाने से सैट–टॉप–बॉक्स और सस्ता हो जाएगा। घरेलू कैस लाइसेंस करीब 32 रुपए या 0.5 डॉलर में प्रदान किया जाएगा जबकि मौजूदा बाजार लागत 2–3 डॉलर प्रति लाइसेंस है। सेट–टॉप–बॉक्स की औसत लागत 800–1,200 रुपए के दायरे में है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक देसी कैस का विकास सरकारी संस्था सी–डैक ने बेंगलुरू की कंपनी बायडिजाइन के साथ मिलकर की है। डेवलपर भारतीय कैस को सभी घरेलू सेट–टॉप–बाक्स विनिर्माताओं और परिचालकों को 0.5 डॉलर प्रति लाइसेंस तक की कीमत पर उपलब्ध कराएंगे। परियोजना की लागत 29.99 करोड़ रुपए है जिसमें से इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 19.79 करोड़ रुपए का योगदान करेगी जबकि शेष राशि का भुगतान बायडिजाइन करेगी।

हाथ के इशारे से चलेगी कार

वर्ष 2016 में बीएमडब्लयू कार हाथ के इशारे से चलेगी। अभी तक बीएमडब्ल्यू में टच स्क्रीन की सुविधा है। लेकिन अब स्क्रीन के सामने इशारे करने से ही बीएमडब्ल्यू की स्मार्ट कार आपकी बात समझ जाएगी। ये फीचर बीएमडब्ल्यू की सिडान कार में मौजूद होगा। एयरटच नाम की नई तकनीक की मदद से यह संभव हो सकेगा। जल्द ही लास वेगास में इस नए फीचर को पेश किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि यह नई तकनीक टच स्क्रीन की तरह की काम करेगी। लेकिन बस फर्क इतना होगा कि आप बिना स्क्रीन को छुए ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइवर सीट के ठीक सामने ही यह स्क्रीन लगी होगी। स्क्रीन के सामने हाथ दिखाते ही यह फीचर काम करना शुरू कर देगा।

रेल यात्रा के दौरान लिजिए सारी सुविधाएं

यात्रियों की सुविधा के लिए एक नया एप 'रेलयात्री' बनाया है। यह रेलवे की दूसरी वेबसाइट से ज्यादा विकसित और फीचर्स से लैस है। यात्री इसे अपने मोबाइल पर गुगल प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप के माध्यम से रेलवे से जुड़ी कई तरह की जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। इस एप की सहायता से रेलयात्री – अलर्ट सिस्टम, लाइव ट्रेन स्टेटस, पीएनआर स्टेटस, समय–सारणी, प्लेटफॉर्म लोकेटर, फूड बुकिंग, सीट उपलब्धता, रेल विस्डम, जीपीएस लोकेटर व स्पीडोमीटर आदि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एलआईसी ने शुरू की जीवन लाभ योजना

जीवन बीमा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सीमित प्रीमियम भुगतान वाली एंडॉवमेंट एश्योरेंस योजना जीवन लाभ की शुरुआत की है। एलआईसी के अनुसार योजना आठ वर्ष से 59 वर्ष आयु वर्ग के लिये उपलब्ध होगी और इसमें 16 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष की अवधि चुनने का विकल्प दिया गया है। इसके साथ ही इसमें संबंधित पॉलिसी धारक को दस, पंद्रह और 16 साल तक प्रीमियम भुगतान करना होगा। योजना के तहत परिपक्वता की अधिकतम आयु 75 साल रखी गई है। अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने पर योजना के तहत दुर्घटना में मत्यू अथवा अंगभंग होने का अतिरिक्त लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा।

कतर देगा को भारत को सस्ती LNG

कतर से भारत को अब सस्ती एलएनजी मिलेगी। इसके लिए कतर की रासगैस और भारत की पेट्रोनेट के बीच नई डील हुई है। रासगैस एलएनजी

की सप्लाई अब 6–7 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पर पेट्रोनेट को करेगी। अभी यह कीमत 12–13 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू है। इसके साथ ही रासगैस ने पेट्रोनेट पर करीब 12,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी समाप्त कर दी है। कांट्रैक्ट से कम गैस इंपोर्ट करने पर रासगैस ने यह पेनल्टी लगाई थी।

एलपीजी इमर्जेंसी हेल्पलाइन नंबर १९०६ लंच

देशभर में कूकिंग गैस कंज्यूमर्स के लिए एलपीजी इमर्जेंसी हेल्पलाइन नंबर 1906 लॉन्च किया गया है। इस नंबर पर कॉल करके कंज्यूमर्स गैस लीकेज जैसी समस्याओं के मामले में

सहायता ले सकते हैं। ऑयल मिनिस्टर धर्मेन्द्र प्रधान ने मिनिस्ट्री और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के टॉप अधिकारियों से इस नंबर को टोल फ्री करने के लिए कहा। हालांकि, अभी इसपर नॉर्मल कॉल रेट्स लागू होंगे।

केरोसिन के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम

सरकार केरोसीन को भी डायरेक्ट ट्रांसफर बनेफिट स्कीम में लाएगी। केरोसीन के ग्राहकों को 1 अप्रैल से इस योजना का लाभ मिलेगा। डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम में ग्राहक मार्केट रेट पर

केरोसीन खरीदेगा वहीं पीडीएस सिस्टम में केरोसीन की कीमत और मार्केट रेट में अंतर को सरकार ग्राहक के बैंक अकाउंट में वापस कर देगी। फिलहाल पीडीएस में केरोसीन की कीमत 12 रुपए प्रति लीटर है। केरोसीन का बाजार भाव करीब 43 रुपए प्रति लीटर है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से केरोसीन पर सब्सिडी के बोझ को कम किया जा सकेगा, क्योंकि इस तरीके से केरोसीन की बिक्री में फर्जीवाड़े की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। 2014–15 में सरकार पर केरोसीन सब्सिडी का बोझ 24799 करोड़ रुपए था। 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, हरियाणा के पानीपत और पंचकुला, हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, उना और झारखंड के कुछ इलाकों में ये स्कीम शुरू की जाएगी।

२०१८ तक सबके पास होगा LPG सिलेंडर

मोदी सरकार ने साल 2016 की शुरुआत में ही हर घर में LPG सिलेंडर पहुंचाने की स्कीम शुरू करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने साल 2016 को 'Year of LPG Consumers' घोषित कर दिया है। अगले तीन साल में देश के बचे हुए करीब 20 करोड़ परिवारों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया जाएगा। देश

में इस समय 27 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। इनमें से 16.5 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां करीब 60 फीसदी आबादी को कवर करती हैं।

हाइवे पर नहीं चलेंगे ओवरलोडेड ट्रक

नेशनल हाइवे पर ओवरलोडेड ट्रकों को रोकने के लिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी (एनएचएआई) ने सख्त कदम उठाए हैं। एनएचएआई ने सभी टोल प्लाजा कांट्रेक्टर्स से कहा है कि वे टोल प्लाजा पर ही ओवरलोडेड ट्रकों की जांच करें। उनसे न केवल 10 गुना

अधिक टोल वसूलें, बल्कि उस ट्रक को रोक कर अपने कब्जे में ले लिया जाए और तबतक आगे न जाने दें, जबतक वह ओवर लोड माल न उतार दे।

हालांकि एक्सपर्टस का मानना है कि इससे ट्रांसपोर्टर्स को लांग टर्म फायदा होगा। इंडियन फाउंडेशन फॉर ट्रांसपोर्ट रिसर्च एवं ट्रेनिंग के सीनियर फेलो एसपी सिंह ने कहा कि ओवरलोडिंग पर अंकुश लगने के बाद ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टर्स को काम मिलेगा। ट्रकों की लाइफ बढ़ जाएगी। टायरों की लाइफ बढ़ जाएगी और रिपेयर मेंटीनेंस का खर्च कम होगा। हाइवे पर दुर्घटनाओं को रोकने, पॉल्यूशन को कम करने और हाइवे की डेमेज को रोकने के लिए सरकार ने 16 दिसंबर 2013 को नोटिफिकेशन जारी किया था।

इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एंबेसडर से हटाए आमिर

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान

अब 'इनक्रेडिबल इंडिया' के ब्रांड एंबेसडर नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार का इस कैंपेन के लिए ऐड एजेंसी मैक्केन वर्ल्डवाइड के साथ कांट्रैक्ट खत्म हो गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने इस खबर की पुष्टि की है। देश में कथित इनटालरेंस को लेकर टिप्पणी के कारण आमिर खान विवाद में आए थे। डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि हमारा अतिथि देवो भव अभियान के लिए मैक्केन वर्ल्डवाइड के साथ कांट्रैक्ट था। एजेंसी ने इस काम के लिए आमिर की सेवा ली थी। अब एजेंसी के साथ कांट्रैक्ट खत्म हो गया है। मंत्रालय ने आमिर की सेवा नहीं ली थी। उन्होंने कहा, यह एजेंसी थी, जिसने उनकी सेवा ली थी। चूंकि एजेंसी के साथ अब अनुबंध नहीं रहा, अभिनेता के साथ व्यवस्था भी अब खुद ब खुद खत्म हो गई है।

सरकार ५,००० टन अरहर दाल का करेगी आयात

उत्पादन घटने की आशंका के कारण दाल की कीमतें अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में सरकार ने घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए 5,000 टन दाल आयात करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। सरकारी कंपनी एमएमटीसी ने टेंडर जारी करते हुआ कहा कि दाल आयात की मात्रा आने वाली बोलियों को

देखते हुए बढ़ाई भी जा सकती है। सरकार को डर है कि 2015 के मुकाबले 2016 में दाल उत्पादन में हल्की बढ़ोतरी से कहीं दाल के दाम दोबारा ऊंचाई पर न पहुंच जाएं। रबी फसल की कम बुआई के कारण दाल का उत्पादन 1.8 करोड़ टन रहने की उम्मीद है, इससे पहले 2014–15 में दाल का उत्पादन 1.73 करोड़ टन रहा था।

याहू कर सकती है 1000 लोगों की छंटनी

सर्च इंजन याहू इंक अपने बिजनेस को दोबारा ट्रैक पर लाने की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में 10 फीसदी की कटौती करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में करीब 1000 से ज्यादा लोगों की नौकरी खतरे में आ सकती है। अमेरिकी कारोबारी समाचार वेबसाइट बिजनेस इंसाइडर ने कहा है कि याहू अपने मीडिया कारोबार, यूरोपीय ऑपरेशन और तकनीकी समूह में छंटनी करने की तैयारी कर रही है। याहू की प्रवक्ता रेबेका न्यूफेल्ड ने कहा कि इस महीने के आखिर में कंपनी की चौथी तिमाही के जारी होने वाले आंकड़े से पहले हम अपनी सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा देंगे। गौरतलब है कि साटरबोर्ड की याहू में 0.75 फीसदी हिस्सेदारी है और वह वर्ष 2014 से व्यापक बदलाव के लिए याहू पर दबाव बना रहा है। उसका कहना है कि याहू अपनी एशियाई परिसंपत्ति को अलग करे तथा कोर बिजनेस की नीलामी करे।

फोर्ब्स की 'अंडर-३०' सूची में ४५ भारतवंशी

भारत के युवा उद्यमियों का डंका हर तरफ बजने लगा है। प्रतिष्ठित फोर्ब्स पत्रिका की ओर से जारी 'अंडर 30' की सूची में 45 भारतीय और भारतवंशियों के नाम शामिल हैं। 30 वर्ष से कम उम्र वाले युवा उद्यमियों की इस पांचवीं वार्षिक सूची में कुल 600 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। इसमें ओयो रूम्स के संस्थापक और सीइओ नीतेश अग्रवाल (22) का भी नाम शामिल है।

फोर्ब्स के मुताबिक सूची में शामिल युवा उद्यमी 20 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। इनमें उपभोक्ता प्रौद्योगिकी, शिक्षा, मीडिया, विनिर्माण एवं उद्योग, विधि, सामाजिक उद्यमशीलता, विज्ञान और कला के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले युवा उद्यमी शामिल हैं। सूची में रितेश के अलावा मोबाइल एप 'स्प्रिग' विकसित करने वाले गगन बियानी और नीरज बेरी के नाम भी हैं।

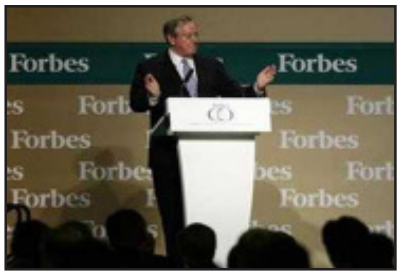

सिटी ग्रुप में उपाध्यक्ष भारतीय मूल की नीला दास (27) और अल्फावेट्स गूगल–एक्स में नियुक्त सबसे युवा अधिकारी 25 वर्षीय करिश्मा शाह भी सूची में जगह पाने में सफल रही हैं।

मुद्रा को बैंक में तब्दील करने के प्रस्ताव मंजूर

छोटे उद्यमियों को कारोबार के विकास में मदद के उद्देश्य से शुरू मुद्रा लिमिटेड को एनबीएफसी से बैंक में तब्दील करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। साथ ही मुद्रा योजना

के तहत दिए जाने वाले ऋणों के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना का भी फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इनके अतिरिक्त एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को बैंकों के जरिए प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया।

एचएमटी की तीन इकाई होंगी बंद

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने एचएमटी की तीन इकाइयों एचएमटी वाचेज, एचएमटी चिनार वाचेज और एचएमटी बियरिंग्स को बंद करने का फैसला लिया है। तीनों ही इकाइयां आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं रह गई थीं। बंद करने की प्रक्रिया के तहत तीनों इकाइयों के कर्मचारियों के लिए आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लाई जाएगी। इसके तहत सभी कर्मचारियों को 2007 के वेतनमान पर आधारित सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने 427.48 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। कंपनी की चल–अचल संपत्ति को सरकारी नीति के मुताबिक निस्तारित किया जाएगा। ❑❑

बाबू गेनू बलिदान दिवस सभा

स्वदेशी जागरण मंच, महालक्ष्मी जिला की ओर से दिनांक 12 दिसंबर 2015 को सायं 5.30 बजे बाबू गेनू के बलिदान दिवस पर सभा का आयोजन बिल्लू धर्मशाला, गोकुलपुरी में किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली एंव हरियाणा संगठक श्री कमलजीत, यमुना विभाग संयोजक श्री मनोज गुप्ता, करावल नगर जिला संयोजक श्री राजीव मिश्र, महालक्ष्मी जिला संयोजक श्री मनीराम नागौरा, श्री मुकेश अरोडा एंव सैकडो स्वदेशी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

श्री कमलजीत ने बाबू गेनू को श्रद्धांजलि के उपरांत सभा को संबोधित करते हुए बताया कि देश को आर्थिक मजबूत करने के लिए स्वदेशी अपनाना होगा। डंकल प्रस्ताव उपरांत आर्थिक उदारीकरण के दौर में सरकारी तौर पर विदेशी कंपनियो पर रोक संभव नही है किन्तु हम स्वदेशी भावना जाग्रत कर लोगों को स्वदेशी वस्तु के उपयोग के लिए प्रेरित कर सकते है। नोवार्टिस कंपनी द्वारा छद्म तरीके से रु. 166000 में कैंसर की दवा बेची जा रही थी जिसे भारतीय कंपनियों ने 6600 रू. में बेचना शुरू किया, जिसकी लडाई स्वदेशी जागरण मंच ने लडी। बडे–बडे जहाज लेकर विदेशी कंपनियों ने बंगाल से लेकर गुजरात तक की समुद्री सीमा पर छोटे–छोटे मछुआरों के रोजगार छीनने का विरोध एवं कंपनियों के खिलाफ आंदोलन स्वदेशी जागरण मंच ने किया।

उन्होंने आगे बताया कि अमेरिका में 35 प्रतिशत आय का श्रोत पेटेंट है, वे साजिश के तहत हल्दी, नीम, बासमती चावल, अदरक, तुलसी आदि के पेटेंट अपने पास लेने की साजिश कर रहे है। हमने उसका विरोध किया है और करते रहेंगे। मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है। महाराष्ट्र में बीटी कॉटन पर जीन संशोधित फसलों की अनुमति दी गई जिसके कारण वहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे विश्व में जीन संशोधित फसलों के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं।

गौधन पर उन्होंने बताया कि AIIMAS नई दिल्ली में केंसर का इलाज गौमूत्र से हो, इसका रिसर्च चल रहा है। कई मरीजों पर प्रयोग सफल रहा है। सतना एवं गुजरात के एक अस्पताल में केंसर का इलाज गौमूत्र से हो रहा है। बहुत ही सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि स्वभिमान के साथ स्वावलंबी बनना हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है।

यमुना विहार विभाग संयोजक श्री मनोज गुप्ता ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए आह्वान किया।

करावल नगर जिला संयोजक राजीव मिश्र ने बताया कि हिन्दुस्तान लीवर कंपनी अपने उत्पाद DOVE साबुन के लिए PALM oil निकालने के लिए इंडोनेशिया तथा अन्य कई देशों में पेडों की कटाई बडे पैमाने पर कर प्रकृति का अवैध दोहन कर रही है। इस कारण कंपनी का भयंकर विरोध है। यह कंपनी इस साबुन को लगभग ८० देशों में बेचती है और भारी मुनाफा कमाती है। पूरे विश्व का 15 प्रतिशत PALM Oil, Dove के लिए यह कंपनी खरीदती है। यह कंपनी 2001 में कोडाइकनल में मरकरी के अवैध डंपिक के लिए दोषी पाई गई थी जिसके कारण वहां ब्रेन ट्यूमर के बहुत मामले सामने आए।

कोका–कोला पर प्रहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस कंपनी के 30 लाख रिटेलर, 56 फैक्टरियां, 35 ब्रांड है, यह हमारे पीने के पानी का 570 बिलियन लीटर पानी का दोहन कर रही है। 1 लीटर कोक पर 9 लीटर शुद्ध पानी खर्च होता है। 2010 के आंकडे के अनुसार 95 हजार लोगों की मौत कोलड्रिंग की वजह से हुई। जलवायु परिवर्तन की बडी गुनहगार ये कंपनियां है जो प्रकृति का अवैध तरीके से दोहन, मुनाफे के लिए कर रही हैं। स्वदेशी जय घोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ❑❑